प्रभात

¡ÂÀÊ §ý qÂÂàà t ....

★ ¥§ýmà §ýàªày-9wã §ýàªày §ýà ¡àœàÂà 4
★ À½»§ýàÊ½u §ý jàn ¡âowÎàÂà §ýL áÊqà¹ 6
★ y÷àâm§ý vh - yÎààoÂàwàÀ §ý âhvàÄý... 9
★ âwÎàx ¡ààn§ý Õàøà qÊ vh 15
★ ykàªà¼ hÀàÂà §ýà rjà¥ 18
★ yvwà k»t §ý ¡àm§ý ¡àÊ §ý¾v¡àt 20
★ qã¥vkã¥ §ýL Îààuq½à §ýàÊwà¢uà 29
★ ÎàÑãÀà §ýà ó÷àkvã 35

sàÊm §ýL §ýÈuâÂàÐ¹ qà¹J (tà¡àwàÀã) À½»§ýàÊ½u ÐqÎàv kàÂàv §ýt¹ã §ýà âmtàÑã th-qøà

wx - 20 ¡§ý - 1 kÂàwÊã-tàj 2007 yÑuàªà ÊààÎà - 10 Úq¥

भारतीय क्रान्ति में मील का पत्थर

sàÊm §ýL §ýÈuâÂàÐ¹ qà¹J (tà¡àwàÀã) §ýL ¥âmÑàây §ý ¥§ýmà §ýàªày - 9wã §ýàªày yÄývmàqw§ý yÈqÂÂà

जनवरी–फरवरी 2007 के बीच भाकपा (माओवादी) की एकता काँग्रेस – 9वीं काँग्रेस का सफल समापन देश और दुनिया की तमाम उत्पीड़ित जनता के लिए ऐतिहासिक महत्व रखने वाला एक ठोस कदम है। इससे पार्टी में हर स्तर पर उन्नत दर्जे की एकता हासिल हुई है। इसी के साथ 21 सितम्बर 2004 को हुई भारतीय क्रान्ति की दो महान धाराओं सीपीआई (एमएल) और एमसीसीआई की एकता अपनी परिणति तक पहुंच चुकी है। इस काँग्रेस ने जीवन्त, जनवादी और कामरेडाना वातावरण में बहस–मुबाहिसे के जरिये पार्टी के भीतर विवादित रहे राजनीतिक मुद्दों का समाधान कर दिया है। 1970 में आयोजित पार्टी की 8वीं काँग्रेस के 36 सालों बाद बुलायी गयी यह काँग्रेस भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में एक और मील का पत्थर है। भारत के माओवादी आन्दोलन के इतिहास में इसकी बड़ी अहमियत है।

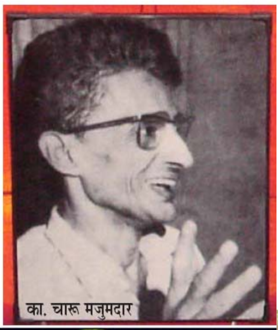
का. चारू मजुमदार

का. कन्हाई चटर्जी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की यह एकता काँग्रेस – 9वीं काँग्रेस देश में स्थापित अनेक छापामार जोनों में से एक जोन में घने जंगलों के बीच आयोजित हुई। 'जन मुक्ति छापामार सेना' की तीन कम्पनियों के सुरक्षा कवच के भीतर तैयार किये गये काँग्रेस के शिबिर, जिसका नाम 'कामरेड चारू मजुमदार–कन्हाई चटर्जी कम्यून' रखा गया था, के चारों ओर चौबीसों घण्टे निगरानी करती अनेक संतरी चौकियाँ, दुश्मन की गतिविधियों की टोह लेते सचल फौजी दस्तों के साथ ही पार्टी के आँख–कान बनी आसपास के तमाम गाँवों की जनता भी लगातार सतर्क रही। इस प्रकार प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के तमाम प्रयासों को नाकाम करते हुए यह काँग्रेस सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। काँग्रेस के चन्द रोज पहले भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी तथा केन्द्रीय मिलिटरी कमीशन के सदस्य कामरेड चन्द्रमौली उर्फ नवीन और उनकी जीवन–साथी

भाकपा (माओवादी) की एकता काँग्रेस – 9वीं काँग्रेस का आह्वान

भारत और दुनिया के उत्पीड़ित अवाम,

साम्राज्यवाद को ध्वस्त करने के लिए जन–ज्वार बनकर उठ खड़े हों!

सारी दुनिया में क्रान्तिकारी जंग को आगे बढ़ाओ!!

तथा डिविजनल कमेटी सदस्या कामरेड करूणा को आन्ध्र प्रदेश के विशेष गुप्तचर ब्यूरो के गुण्डों ने गिरफ्तार कर, क्रूर यातना देकर हत्या कर डाली थी। सरकार के यातना गृहों में मजबूती से खड़े रहने वाले इन दो कामरेडों ने जनता तथा पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने प्राण त्याग दिये थे। उनकी इस महान कुर्बानी का भी काँग्रेस के सफल आयोजन में बड़ा योगदान रहा। इसी कड़ी में काँग्रेस के भवन को कामरेड चन्द्रमौली और अक्टूबर 2005 में शहीद हुए पार्टी की केन्द्रीय कमेटी तथा पोलितब्यूरो के सदस्य कामरेड शमशेर सिंह शेरी उर्फ करम सिंह के नाम देते हुए 'कामरेड करम सिंह-चन्द्रमौली भवन' कहा गया।

काँग्रेस का यह आयोजन दुश्मन की जबरदस्त घेराबन्दी के बीच हुआ, जिसे रोकने के लिए सरकार ने एक विशेष सेल का भी गठन कर रखा था। पार्टी के सभी छापामार जोनों के इर्द-गिर्द विशेष निगरानी रखते हुए गुप्तचर विभाग आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर बारीकी से नजर रख रहा था। मीडिया तक में काँग्रेस की सम्भावित तिथियों की अटकलें व्यक्त की जा रही थीं। इस सबके बावजूद व्यापक घेराबन्दी के बीच भी 16 प्रदेशों से 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों समेत भारत के माओवादी आन्दोलन का यह शीर्षस्थ नेतृत्व सभा-स्थल तक पहुंचने में कामयाब हो सका।

इस एकता काँग्रेस का उद्घाटन पार्टी के निवर्तमान महासचिव कामरेड गणपति ने किया। कामरेड किशन ने उपस्थित समूह को सम्बोधित किया। फिर शहीद स्मारक स्तम्भ पर पुष्प अर्पित किये गये और पिछली, 8वीं काँग्रेस के बाद के अन्तराल में अपने प्राणों की आहूति देने वाले महान शहीद कामरेडों को मान-सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गयी। इसके बाद गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकालते हुए तमाम प्रतिनिधि करम सिंह-चन्द्रमौली काँग्रेस भवन तक पहुंचे, जहां कई दिनों तक चर्चाएं चलती रहीं।

इस ऐतिहासिक काँग्रेस ने एकीकश्त पार्टी के पाँच बुनियादी दस्तावेजों को खुली व बेबाक चर्चाओं और सघन विचार-विमर्श के बाद पारित किया। इस प्रकार पार्टी के निम्न दस्तावेज – 'मार्क्सवादी-लेनिनवाद-माओवाद के चमकते लाल झण्डे को ऊँचा उठाओ!', 'पार्टी कार्यक्रम', 'पार्टी संविधान', 'भारतीय क्रान्ति की रणनीति और कार्यनीति', देश-दुनिया की ताजी घटनाओं को समेटते हुए 'राजनीतिक प्रस्ताव' – पारित किये गये।

काँग्रेस ने सन् 1969 में दोनों पूर्ववर्ती माओवादी पार्टियों के गठन से लेकर आज तक के कार्यों की समीक्षा, पूर्ववर्ती पीडब्ल्यू की काँग्रेस के बाद 2001 से 2004 तक के कार्यों की समीक्षा और नवगठित पार्टी के पिछले दो वर्षों के कार्यों की समीक्षा पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया। इसके अलावा काँग्रेस ने देश और दुनिया के मौजूदा महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किये और कुछ जरूरी सांगठनिक तब्दीलियों समेत नयी केन्द्रीय कमेटी का चुनाव किया। काँग्रेस पिछले दो सालों से पार्टी में ऊपर से नीचे तक चल रही उस प्रक्रिया की अपेक्षित परिणति रही, जिसके तहत इलाकाई, जिला, क्षेत्रीय तथा प्रदेश स्तर पर गम्भीर चर्चा हुई और सम्मेलन आयोजित हुए। इस प्रकार नीचे से भी काँग्रेस में चर्चा के लिए सैकड़ों संशोधन भेजे गये थे।

इस एकता काँग्रेस ने 1967 के नक्सलबाड़ी जन उभार से भारतीय क्रान्ति की कार्यसूची पर आ उपस्थित हुए दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते और कृषि क्रान्ति की धुरी पर नयी जनवादी क्रान्ति की आम कार्यदिशा को नयी बुलन्दी के साथ अपना

एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस के केन्द्रीय नारे

- ✶ **पार्टी कमेटियों को पहलकदमी लेने वाली, स्वावलम्बी कमेटी बनायें और अपने क्षेत्र विशेष के आन्दोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए सक्षम बनायें!**
- ✶ **दण्डकारण्य और बिहार-झारखण्ड में आधार क्षेत्र का निर्माण करें !**
- ✶ **पीएलजीए को पीएलए मे बदल दें!**
- ✶ **जनयुद्ध की ओर उन्मुख मजबूत शहरी क्रान्तिकारी आन्दोलन का निर्माण करें!**
- ✶ **मुख्य जोनों में जन युद्ध को आगे बढ़ाते हुए चार वर्गों के संश्रय के रूप में संयुक्त मोर्चा विकसित करें और स्थानीय से लेकर जोन के स्तर तक क्रान्तिकारी जन कमेटियाँ स्थापित तथा मजबूत करें!**
- ✶ **तमाम क्षेत्रों में भारतीय शासक वर्गो द्वारा चलाये जा रहे फासीवादी दमन के खिलाफ व्यापक जनता को जुझारू संघर्षो में गोलबन्द करें और समस्त निरंकुश कानूनों के विरुद्ध अडिग संघर्ष करें!**
- ✶ **जातिगत उत्पीड़न के सभी रूपों के विरुद्ध दलितों को संगठित करें!**
- ✶ **महिलाओं को पितृसत्ता और सामन्ती/साम्राज्यवादी उत्पीड़न के सभी रूपों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गोलबन्द करें!**
- ✶ **कश्मीर, असम, नागालैण्ड, मणिपुर और उत्तर-पूर्व के अन्य हिस्सों में चल रहे विभिन्न राष्ट्रीयताओं के सशस्त्र संघर्षो के साथ दीर्घकालीन लोकयुद्ध का तालमेल करें!**
- ✶ **हिन्दू फासीवाद के खिलाफ अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों के व्यापक मोर्चे का निर्माण करें!**

लिया। इसने पार्टी की राजनीतिक-सामरिक कार्यदिशा को समृद्ध किया और पार्टी के समक्ष अनेक कार्यभार उपस्थित किये। समूची पार्टी के सामने आधार इलाकों की स्थापना को फौरी, बुनियादी तथा केन्द्रीय कार्यभार के रूप में रखते हुए उस पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसी के साथ काँग्रेस ने देश भर में जन युद्ध को आगे बढ़ाने, जन सेना को अधिक मजबूत करने, पार्टी के जनाधार को अधिक सघन बनाने और साम्राज्यवाद के इशारों पर प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों द्वारा लागू की जा रही वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नवउदारपंथी नीतियों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर जुझारू जन आन्दोलन छेड़ने का भी संकल्प लिया।

पार्टी के दस्तावेजों में जोड़ी गयी अथवा विकसित की गयी निम्नलिखित बातें गौरतलब हैं :

* भारतीय सामन्तवाद/अर्द्ध-सामन्तवाद को जाति-प्रथा तथा ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ गहराई से गुँथा हुआ मानते हुए उसकी विशिष्ट चारित्रिक विशेषता को इस प्रकार पहचाना गया – ''यहां जातिगत उत्पीड़न और ब्राह्मणवाद मौजूदा अर्द्ध-सामन्ती, अर्द्ध-औपनिवेशिक व्यवस्था के साथ अविच्छिन्न रूप से गुँथा हुआ है। जाति व्यवस्था केवल अधिरचनात्मक परिघटना ही नहीं है, बल्कि आर्थिक आधार का भी हिस्सा है। इस वजह से छुआछूत के उन्मूलन के साथ ही साथ जाति व्यवस्था का नाश और ब्राह्मणवाद की सभी अभिव्यक्तियों के खिलाफ संघर्ष हमारे देश में नयी जनवादी क्रान्ति का आवश्यक अंग है।''

वर्गों और जातियों के बीच सम्बन्धों के बारे में; उत्पीड़ित जातियों को अपने सामाजिक उत्पीड़न के अलावा जो अधिक आर्थिक शोषण झेलना पड़ता है, उसके बारे में और अन्य सम्बन्धित पहलुओं के बारे में पहले से अधिक स्पष्ट रूप से व्याख्या दी गयी है। संयुक्त मोर्चे के निर्माण में दलितों तथा उत्पीड़ित जातियों को खास तौर पर लाने के महत्व को पहचाना गया। दलित संगठनों के साथ मिलकर काम करने, दलित आन्दोलनों में हिस्सेदारी करने और छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव के खिलाफ तथा जाति-प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले विशिष्ट संगठनों का निर्माण करने का निश्चिय किया गया।

* कृषि में, खास कर पंजाब में हो रहे परिवर्तनों का अर्द्ध-सामन्ती ढांचे के तहत आकलन करते हुए पार्टी की कार्यनीति पर इसके प्रभाव को समझा गया।

* भारतीय सन्दर्भ में दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग पर अधिक स्पष्टता हासिल की गयी। यह व्याख्यायित किया गया कि किस प्रकार दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग तथा बड़े जमींदार दोनों ही साम्राज्यवाद के मुख्य वाहक हैं और कैसे भारतीय राज्य इन दोनों वर्गों की संयुक्त तानाशाही है।

* छापामार आधार-क्षेत्र, आधार इलाका, दोहरी सत्ता आदि अवाधारणाओं पर समझदारी खास कर भारतीय सन्दर्भों में गहरायी गयी। मसौदा दस्तावेज में छापामार जोन में दोहरी सत्ता के विषय में जो विसंगति रही है उसे दूर किया गया और अधिक स्पष्टता हासिल की गयी। छापामार आधार-क्षेत्रों के संक्रमणकालीन स्वरूप को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया। विभिन्न छापामार जोनों तथा परिप्रेक्ष्य आधार इलाकों के बीच सम्बन्धों की साफ तस्वीर प्रस्तुत की गयी।

* केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा छेड़े गये सर्वाधिक नृशंस, प्रतिक्रान्तिकारी, चौतरफा युद्ध के चलते आन्ध्र प्रदेश के आन्दोलन को लगे मौजूदा धक्के से कैसे उबरा जाय इस पर चर्चा की गयी। निम्न तीव्रता के युद्ध के रूप में दुश्मन के चौतरफा युद्ध के बारे में और इसे पराजित करने के लिए अपनायी जाने वाली हमारी कार्यनीति के विषय में रेशा-रेशा चर्चा की गयी। मैदानी क्षेत्रों में अपनायी जाने वाली कार्यनीति, मैदानों में चलाये जाने वाले छापामार युद्ध इत्यादि की उसूली समझ बनायी गयी।

* जन युद्ध को आगे बढ़ाने तथा जन मुक्ति छापामार सेना को जन मुक्ति सेना में, छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में एवं छापामार जोनों को आधार इलाकों में तब्दील करने का लक्ष्य तय किया गया।

* मजदूर वर्ग, संयुक्त मोर्चे और अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने के महत्व तथा सार्थकता को रेखांकित किया गया।

इस काँग्रेस ने बहुत सारी ताजी घटनाओं पर राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किये। इनमें दुनिया के जन संघर्षों पर प्रस्ताव, राष्ट्रीयता के संघर्षों को समर्थन, भारतीय विस्तारवाद के खिलाफ प्रस्ताव, खैरलांजी की घटना के बाद दलित उभार तथा जातिगत उत्पीड़न के विषय में प्रस्ताव, हिन्दू फासीवाद के खिलाफ प्रस्ताव, विशेष आर्थिक जोनों तथा विस्थापन के विरुद्ध प्रस्ताव शामिल हैं। इनके अलावा क्रान्ति के तीन जादुई हथियारों – पार्टी, सेना, संयुक्त मोर्चे – को मजबूत करने पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। सदन के समक्ष एकीकृत पार्टी का पिछले दो वर्षों का आय-व्यय पत्रक प्रस्तुत किया गया। इसके बाद निवर्तमान केन्द्रीय कमेटी ने अपनी सामूहिक आत्म-आलोचना पेश की, अपनी कमजोरियों के मुख्य-मुख्य बिन्दुओं को प्रस्तुत किया और काँग्रेस के प्रतिनिधियों से इस पर अपनी आलोचना पेश करने के लिए आग्रह किया। इस प्रक्रिया को सम्पन्न करने पर नयी केन्द्रीय कमेटी का चुनाव हुआ। नयी केन्द्रीय कमेटी ने कामरेड गणपति को पार्टी के महासचिव के रूप में दुबारा चुन लिया।

'साम्राज्यवाद और उसके तमाम दुमछल्लों को ध्वस्त करने के लिए जन-ज्वार बनकर उठ खड़े हों! दुनिया भर में क्रान्तिकारी युद्ध को आगे बढ़ाओ!!' – दुनिया की जनता का इस प्रकार आह्वान करते हुए बड़े जोशोखरोश के साथ काँग्रेस का समापन हुआ। अन्ततः भाकपा (माओवादी) की इस एकता काँग्रेस - 9वीं काँग्रेस ने साम्राज्यवाद तथा अर्द्ध-सामन्ती बेड़ियों से मुक्त, न्याय और समानता पर आधारित, सचमुच के जनवादी समाज का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ देश में छेड़े जा रहे जन युद्ध और अंकुरित की जा रही जन सत्ता का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता का बड़ी तादाद में आगे आने का आह्वान किया।

(गणपति)

महासचिव

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

दिनांक : 17 फरवरी 2007

<u>भाकपा (माओवादी) की एकता काँग्रेस - 9वीं काँग्रेस का आह्वान</u>

भारत और दुनिया के उत्पीड़ित अवाम,
साम्राज्यवाद को ध्वस्त करने के लिए जन-ज्वार बनकर उठ खड़े हों !
सारी दुनिया में क्रान्तिकारी जंग को आगे बढ़ाओ !!

उत्पीड़ित राष्ट्रों और दुनिया के अवाम!

साम्राज्यवाद और उसके तमाम दुमछल्लों के खिलाफ दुनिया भर में और एशिया, अफ्रीका तथा लातिन अमेरिका के देशों में वहां के प्रतिक्रान्तिकारियों के खिलाफ आप जिन न्यायसंगत व जनवादी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, उन सभी को भाकपा (माओवादी) की यह एकता काँग्रेस - 9वीं काँग्रेस सलाम पेश करती है। साम्राज्यवादी अत्याचारियों के खिलाफ खास कर इराक, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, लेबनान और अन्य कई देशों में आप अपने अविराम, समझौताविहीन संघर्षों से इतिहास की नये सिरे से रचना कर रहे हैं। आपके बहादुराना राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों ने साम्राज्यवाद को ऐसे दलदल की ओर धकेल दिया है जहां से बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की शन्ति-प्रिय जनता! आप साम्राज्यवादी आक्रमण, हस्तक्षेप, षड़यंत्र तथा धौंस-धमकी के खिलाफ; ''आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी जंग'' के नाम पर दुनिया के अवाम पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा थोपे गये तमाम अन्यायपूर्ण युद्धों के खिलाफ; साम्राज्यवादियों तथा उनकी संस्थाओं विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन आदि द्वारा विभिन्न देशों पर थोपी गयी नवउदारपंथी नीतियों के खिलाफ तमाम लोग जो संघर्ष छेड़े हुए हैं उन सभी के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। भारत की 110 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती भाकपा (माओवादी) की यह काँग्रेस बुलन्दी के साथ ऐलान करती है कि हम साम्राज्यवाद के खिलाफ खास कर सबसे बड़े अन्तरराष्ट्रीय आतंकवादी और दुनिया के अवाम के नम्बर एक दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आपके युद्ध में हम हमेशा आपके ही साथ रहेंगे। यह काँग्रेस साम्राज्यवाद तथा भारत के सत्ताधारी दलालों को ध्वस्त करने के लिए भारत में जन युद्ध को सघन रूप से चलाने का प्रण करती है। आइये हम दुनिया भर में साम्राज्यवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए कतारों को एकजुट करें और शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त वर्गविहीन समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करें!

'हजारों शहीद बड़ी बहादुरी के साथ जनता के लिए अपनी जिन्दगी न्यौछावर कर चुके हैं। आइये, हम उनका झण्डा बुलन्द रखें और उनके खून से सींचे हुए रास्ते पर आगे बढ़ते जायें' *—कामरेडमाओत्से-तुङ*

भारत के उत्पीड़ित अवाम और तमाम राष्ट्रीयताएं!

यह एकता काँग्रेस आप सभी की न्यायसंगत मांगों तथा संघर्षों – मजदूर वर्ग, किसानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, राष्ट्रीयताओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, छात्रों, युवाओं, बुद्धिजीवियों और साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद, सामन्तवाद के वर्चस्व में कायम यहां की उत्पीड़नकारी अर्द्ध-औपनिवेशिक, अर्द्ध-सामन्ती व्यवस्था के तहत अकथनीय दुख-तकलीफ उठा रहे समाज के अन्य तमाम उत्पीड़ित तबकों की समस्त मांगों तथा संघर्षों का एक स्वर से समर्थन करती है। यहां के शासक वर्ग साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की जिन नीतियों को लागू कर रहे हैं उनसे आपकी जिन्दगी इस कदर तबाह हो रही है, जिसकी 1947 के बाद के भारत में कोई सानी नहीं रही है। केन्द्र या प्रदेशों में सत्ता किसी भी पार्टी के हाथों में रहे, देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में इन्हीं नीतियों को आक्रामक रूप से थोपा जा रहा है।

भारत के विस्तारवादी शासक वर्ग साम्राज्यवाद के सम्पूर्ण समर्थन और आशिर्वाद से विभिन्न राष्ट्रीयताओं की जनता पर हिंसा तथा आतंक के बद से बदतर रूपों को अपना रहे हैं। काश्मीर, असम, मणिपुर तथा नागालैण्ड में खून बहता जा रहा है। केन्द्र के अर्द्ध-सैनिक जरखरीद बलों और भारतीय सेना द्वारा हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। यह काँग्रेस उन तमाम राष्ट्रीयता के आन्दोलनों और अलग होने के अधिकार समेत आत्मनिर्णय के उनके अधिकार का तहे दिल से समर्थन करने का एक बार फिर ऐलान करती है। यह भारतीय विस्तारवाद के खिलाफ दक्षिण एशिया की जनता का समर्थन करती है और भारतीय विस्तारवाद के खिलाफ संघर्ष के अग्रिम पंक्ति में रहने के लिए भारतीय अवाम का आह्वान करती है।

साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित नीतियों से सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हैं हमारे गरीब तथा भूमिहीन किसान जो हजारों की तादाद में आत्महत्या तक करने को विवश हो रहे हैं और भूख और

> **''आज क्रांति प्रतिक्रांति का मुकाबला कर रही है। एक ओर भारत की जनता हमें एक विकल्प के रूप में देख रही है, तो दूसरी ओर दुश्मन हमें पूरी तरह खत्म करने के इरादे से चौतरफा हमला कर रहा है। हम भारतीय राजसत्ता की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी काँग्रेस आयोजित कर रहे हैं। भारतीय शोषक-शासक वर्ग किसी भी कीमत पर काँग्रेस पर हमला करके समूची पार्टी के नेतृत्व को खत्म करने की मंशा पाल रहा है। लेकिन हम इस भयंकर दमन के बीच भी नीचे से ऊपर तक सम्मेलनों की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से काँग्रेस सम्पन्न करने के लिए दृढ़ सकंल्प हैं।''**
>
> - §ýàªày §ýà £Ài à¹|Àà §ýÊm Ñ¥ tÑàyâjw §ýàtÊ»| ªà½àqâm

भुखमरी के चलते अकथनीय दुर्दशा का जीवन जी रहे हैं। भाकपा (माओवादी) की यह काँग्रेस तमाम उत्पीड़ित किसानों से आह्वान करती है कि अपने उत्पीड़कों का नामोनिशान मिटाने के लिए इन नीतियों के खिलाफ एक तूफान की तरह उठ खड़े हों और गाँव-गाँव में अपनी राजनीतिक जन सत्ता कायम करें।

समूचा मजदूर वर्ग श्रम के भारी पैमाने पर ठेकाकरण, वेतन की स्थिरता, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति, निष्कासन, भर्ती पर रोक, अदालतों के श्रमिक-विरोधी फैसलों, हड़तालों पर अघोषित प्रतिबन्ध आदि के चलते अधिकाधिक कंगाली की ओर धकेले जा रहे हैं।

उड़ीसा में पॉस्को, कलिंगनगर, बॉक्साइट खदानों; छत्तीसगढ़ के चारगाँव तथा रावघाट में बॉक्साइट खदानों; आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना; झारखण्ड में लोहे के खदान तथा यूरेनियम परियोजनाओं जैसी भारी-भरकम परियोजनाओं के चलते आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है, उन्हें हाशिये पर फेंक दिया जा रहा है। यही नहीं देश में 300 विशेष आर्थिक जोनों की योजना है, जहां हमारी ही सरजमीं पर विदेशी इलाके तैयार किये जायेंगे। इसके लिए विदेशी तथा स्थानीय भूमाफिया खेती की अच्छी-खासी जमीन में से लाखों एकड़ पर कब्जा करने को तैयार बैठे हैं। इसके अलावा शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों और पक्के घरों तक को निर्मम तरीके से गिराया जा रहा है और लाखों की तादाद में लोगों को बेदखल किया जा रहा है। बड़े व्यवसायी घरानों तथा साम्राज्यवादी कम्पनियों एवं खुदरा विक्रय केन्द्रों का जाल बिछाने के लिए इस प्रकार रास्ता साफ किया जा रहा है। यह नौवीं काँग्रेस इस व्यापक बेदखली का प्रतिरोध करने के लिए और अपनी जमीन, जंगल और घर-मकान की लुटेरों से रक्षा करने के लिए आदिवासियों, किसानों तथा शहरी गरीबों का आह्वान करती है।

साम्राज्यवादी और सामन्ती संस्कृति के फलस्वरूप महिलाओं का शोषण एवं पितृसत्तात्मक उत्पीड़न बहुत हद तक बढ़ गया है। तथाकथित दहेज हत्याओं, महिलाओं का अधिकाधिक यौन शोषण और राज्य तथा सामन्ती एवं पुरुष अहंकारवादी शक्तियों की ओर से बढ़ती हिंसा तथा भेदभाव के कारण महिलाओं के उत्पीड़न में बेशुमार बढ़ोतरी हुई है। यह काँग्रेस महिलाओं से आह्वान करती है कि इस शोषण, उत्पीड़न तथा भेदभाव के खिलाफ उठ खड़ी हों और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलन्द करें।

हाल में बढ़ते दलित उभार के साथ-साथ दलितों पर हमलों और छुआछूत जैसे अमानवीय प्रथा में भी बहुत हद तक बढ़ोतरी हुई है। यह काँग्रेस खैरलांजी के हत्याकाण्ड और कानपुर में अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़े जाने के बाद दलितों के व्यापक जन उभार का बुलंदी से स्वागत करती है। यह समस्त दलितों से आह्वान करती है कि इन बढ़ते हमलों तथा भेदभाव का जुझारू तरीके से प्रतिरोध करने के लिए क्रान्तिकारी झण्डे के तले लामबन्द हों।

बेरोजगारी, अल्परोजगारी, सांस्कृतिक पतन, कैरियरवाद और हताशा के चलते देश के छात्रों एवं युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। साम्राज्यवादी/दलाल नौकरशाह पूंजीवादी आक्रमण के चलते लाखों छोटे उद्योग तथा व्यापारी दीवालियेपन की चपेट में हैं। इसी तरह जनता के अन्य तमाम तबके साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के जुए के नीचे पिस रहे हैं। भाकपा (माओवादी) की यह 9वीं काँग्रेस छात्रों, नौजवानों और अन्य तमाम तबकों से आह्वान करती है कि भारतीय अवाम के इन दुश्मनों के खिलाफ एकजुट संघर्ष छेड़ें और उनकी समस्याओं के एकमात्र समाधान के तौर पर नये जनवादी समाज की रचना करने के लिए क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल हों।

भारतीय अवाम की व्यापक जनसंख्या के अंग के रूप में हम सभी को हमारे देश के जीवन के हरेक पहलू पर साम्राज्यवादियों, खास कर अमेरिका के लगातार कसते शिकंजे को तोड़ने के लिए एकजुट होकर जुझारू संघर्ष करना होगा। भारत की जनता जब साम्राज्यवादी हमलों और यहां के प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के फासीवादी हमलों का साहस के साथ प्रतिरोध कर रही हो, तो भाकपा (माओवादी) उनके साथ मजबूती से खड़े होने और उनका हर सूरत में नेतृत्व करने का संकल्प लेती है। भारतीय जनता से भाकपा (माओवादी) की यह एकता काँग्रेस - 9वीं काँग्रेस आह्वान करती है कि दुनिया भर में अमेरिकी साम्राज्यवाद की आक्रामक युद्धोन्मादी नीतियों की पुरजोर भर्त्सना करें और खास कर इराक, अफगानिस्तान, लेबनान और फिलिपीन्स के जन प्रतिरोध का समर्थन करें।

अंततः भाकपा (माओवादी) की यह 9वीं काँग्रेस भारतीय जनता से आह्वान करती है कि देश में चल रहे जन युद्ध और जनता की अंकुरीत हो रही राजनीतिक सत्ता का बड़ी से बड़ी तादाद में समर्थन करें, इस संघर्ष को व्यापक बनायें तथा आगे बढ़ायें ताकि न्याय और समानता पर आधारित, साम्राज्यवाद तथा अर्द्ध-सामन्ती गुलामी की बेड़ियों से मुक्त सचमुच के जनवादी समाज का निर्माण किया जा सके।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की

एकता काँग्रेस - 9वीं काँग्रेस

"जनयुद्ध को तेज करो – दण्डकारण्य को आधार इलाके में बदल डालो"

दण्डकारण्य के चौथे अधिवेशन में गूंज उठा नारा

दण्डकारण्य में माओवादी आन्दोलन का सफाया करने की मंशा से केन्द्र एवं छत्तीसगढ़–महाराष्ट्र राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे घोर दमन अभियानों के बीचोबीच, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दण्डकारण्य स्पेशल जोन का चौथा अधिवेशन 23 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2006 तक कामयाबी के साथ सम्पन्न हुआ. भारतीय क्रान्ति की दो धाराओं भाकपा (मा–ले) की धारा और एमसीसीआई की धारा की मिलन तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उदय के बाद दण्डकारण्य स्पेशल जोन का यह पहला अधिवेशन था. यह अधिवेशन ऐसे समय सम्पन्न हुआ,जबकि लुटेरे शासक वर्गों ने साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों की देखरेख में 'सलवा जुडूम' के नाम से दण्डकारण्य के आदिवासी अवाम पर एक अत्यंत पाशविक हमला छेड़ रखा है. जून 2005 से जारी इस बर्बरतापूर्ण एवं फासीवादी हमले में अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं. हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी और आतंक का तांडव चारों ओर मचा हुआ है. कार्पेट सेक्यूरिटी के नाम से खासकर दक्षिण और पश्चिम बस्तर के इलाके पुलिस एवं अर्ध–सैनिक बलों की छावनियों में तब्दील हो चुके हैं. इसके जवाब में पीएलजीए और कोया भूमकाल मिलिशिया के नेतृत्व में जनता का प्रतिरोधी संघर्ष भी लगातार जारी हैं. दर्जनों पुलिस बलों, एसपीओ और गुण्डों को मार गिराया जा रहा है. दूसरी तरफ दुश्मन केपीएस गिल जैसे कातिल अफसरों को सलाहकार नियुक्त कर, हजारों अर्ध–सैनिक बलों को उतारकर सैन्य हेलिकॉप्टरों एवं मानवरहित विमानों के जरिए सभी इलाकों में निगरानी बढ़ा दी. इन सबके बीच घने जंगलों और पहाड़ों के बीच निर्मित 'कॉमरेड करमसिंह कम्यून' में दण्डकारण्य स्पेशल जोन का चौथा अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ. इसमें भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को कई दिनों तक पैदल मार्च करना पड़ा और दुश्मन के अनेक घेराव अभियानों को तोड़ते हुए आना पड़ा. दक्षिण एवं पश्चिम बस्तर डिवीजनों से आ रहे प्रतिनिधि कॉमरेडों पर एक जगह पुलिस व अर्ध सैनिक बलों का हमला भी हुआ था. उस हमले का मुकाबला कर कर ही वे यहां पहुंच पाए.

चौथे अधिवेशन का उद्घाटन समारोह

दिन 23 सितम्बर 2007 था. सबेरे से ही कॉमरेड करमसिंह कम्यून में हलचल थी. पूरे कम्यून को पीएलजीए के सैनिक तोरणों व लाल वंदनवारों से सजा रहे थे. जगह–जगह शहीदों के नाम पर द्वार बनाए जा रहे थे. अधिवेशन हाल बनाकर उसे सजाया जा रहा था, जो अन्तिम चरण में था. अधिवेशन हाल के बाजू में शहीद वेदी का निर्माण किया गया था. पूरे परेड ग्राउण्ड को वंदनवारों से सजाकर बीच में झण्डा फहराने का प्रबन्ध किया गया था. केन्द्रीय कमेटी, डीके एसजेडसी (स्पेशल जोनल कमेटी) और पीएलजीए साथियों के टेन्ट व्यवस्थित ढंग से लगे थे. सभी टेन्ट हमारी पार्टी के शहीद साथियों के नाम पर थे. 'दण्डकारण्य को आधार इलाका बनाएंगे' के बैनर के अलावा जगह–जगह क्रान्तिकारी नारों के पोस्टर, प्लाकॉर्ड टंगाए गए थे. पूरा माहौल क्रान्तिकारी जोशोखरोश से भरा हुआ था. जहां एक तरफ दूर–दूर तक पीएलजीए के बहादुर सैनिक अधिवेशन की चौकसी में चारों ओर

पिछले 6 सालों में दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन द्वारा हासिल खास उपलब्धियां

- **ग्राम स्तर से लेकर जोनल स्तर तक पार्टी संगठन मजबूत हुआ. सभी स्तरों में पार्टी कमेटियों का विकास हुआ.**
- **क्रान्तिकारी आन्दोलन का जड़ से सफाया करने की मंशा से दुश्मन द्वारा 2003 से लगातार जारी विभिन्न दमन-मुहिमों को पराजित करते हुए जनयुद्ध को अपेक्षाकृत उन्नत स्तर में विकसित करने में हम कामयाब हुए. इस दौरान पीएलजीए की ताकत संख्या में, गुण में एवं शस्त्रास्त्रों की दृष्टि से अपेक्षाकृत बढ़ी है.**
- **हजारों की संख्या में जन मिलिशिया का गठन किया गया है. दुश्मन के बलों के खिलाफ चलाए गए विभिन्न कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियानों में लड़ते हुए जन मिलिशिया मजबूत हो गई. दण्डकारण्य में आज जन मिलिशिया पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों के लिए बुरा स्वप्न बन गई है.**
- **गांव स्तर पर लुटेरे वर्गों की राजसत्ता को खत्म करते हुए व्यापक इलाकों में जनता की नई राजसत्ता के अंगों, यानि जनतना सरकार की इकाइयों का गठन किया गया. उन्हें मजबूत करते हुए विस्तारित करने की प्रक्रिया लगातार जारी है.**
- **जन संघर्षों में जनता को बड़े पैमाने पर गोलबन्द करते हुए विभिन्न जन संगठनों को मजबूत किया गया. ग्राम स्तर से जोनल स्तर तक जन संगठनों का मजबूत ढांचा तैयार हो गया. मुद्दों के आधार पर विभिन्न तबकों के लोगों को गोलबन्द कर कई जन संघर्षों का संचालन किया गया.**

लगे हुए थे, वहीं आसपास के गांवों की जनता, जन संगठन एवं जन मिलिशिया ने भी इस आयोजन की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर दिन-रात पहरेदारी की. इनकी इजाजत के बिना परिंदा भी अधिवेशन हाल तक नहीं पहुंच सकता था.

ठीक 4 बजे शाम को कॉमरेड सुखदेव परेड ग्राउण्ड में केन्द्रीय कमेटी सदस्य, डीके एसजेडसी के सदस्य, दण्डकारण्य के सभी डिवीजनों एवं विभागों से आए प्रतिनिधि, सांस्कृतिक दल (सीएनएम) के कॉमरेड तथा सुरक्षा के लिए आए पीएलजीए के सैनिक जमा हो गए. वहां से पूरे कम्यून में जुलूस निकाला गया. जुलूस के आगे-आगे डीके एसजेडसी के सदस्य,जिनकी अगुवाई सचिव कॉमरेड कोसा कर रहे थे, चल रहे थे. उनके पीछे-पीछे सांस्कृतिक दल के सदस्य अपने विशिष्ट पोशाकों में पैरों में घुंघरू बांधकर हाथों में ढफली, ढोलक, नगाड़ा, तुड़ुम जैसे परम्परागत गाजे-बाजे के साथ नाचते-गाते, नारे लगाते आगे बढ़ रहे थे. उनके पीछे पीएलजीए के कॉमरेड और प्रतिनिधिगण गगनभेदी नारों से चल रहे थे. 'भाकपा (माओवादी) जिन्दाबाद', 'कॉमरेड्स चारु मजुमदार - कनाई चटर्जी अमर रहें', 'भारत की नव जनवादी क्रान्ति जिन्दाबाद', 'दण्डकारण्य में पनप रही जनता की जनवादी सत्ता - जनतना सरकार जिन्दाबाद', 'सलवा जुडुम को हराएंगे', 'दण्डकारण्य को आधार इलाका बनाएंगे', 'पीएलजीए को पीएलए में बदल डालेंगे', 'साम्राज्यवाद मुर्दाबाद', आदि-आदि क्रान्तिकारी नारों से सारा करमसिंह कम्यून गूंज उठा. जुलूस पूरे एक वर्ग किलोमीटर तक फैले कम्यून का चक्कर लगाने के बाद फिर से कॉमरेड सुखदेव परेड ग्राउण्ड पहुंचा. वहां पीएलजीए कमाण्डर के काशन पर सभी कॉमरेड अनुशासनबद्ध तरीके से 3 कतारों में खड़े हो गए. बाद में डीके एसजेडसी के सचिव कॉमरेड कोसा ने भाकपा (माओवादी) के दण्डकारण्य स्पेशल जोन के चौथे अधिवेशन के शुरू होने की विधिवत् घोषणा करते हुए झण्डा फहराया. सारा कम्यून अन्तर्राष्ट्रीय गान से गूंज उठा. केन्द्रीय कमेटी के एक वरिष्ठ कॉमरेड ने केन्द्रीय कमेटी की तरफ से संदेश दिया और अधिवेशन की सफलता की कामना की.

अधिवेशन ने निम्नांकित नारे अपनाए -

- **दण्डकारण्य को आधार इलाका बनाएंगे !**
- **छापामार युद्ध को चलायमान युद्ध में बदलेंगे !**
- **पीएलजीए को पीएलए में तब्दील करेंगे !**
- **दण्डकारण्य में पनप रही जनता की नई जनवादी सत्ता को मजबूत करेंगे - फैलाएंगे !**
- **राजनीतिक संघर्षों एवं रोजमर्रा के संघर्षों में विभिन्न तबकों के लोगों को बड़े पैमाने पर गोलबन्द करते हुए एक विशाल साम्राज्यवाद-विरोधी एवं सामन्तवाद-विरोधी मोर्चे की नींव डालेंगे !**

चौथे अधिवेशन का उद्‌घाटन समारोह

परेड ग्राउण्ड के कार्यक्रम के बाद जुलूस अधिवेशन हाल के नजदीक बनी शहीद वेदी के पास पहुंचा, जहां पर वीर शहीदों को श्रद्धासुमन पेश करने का संजीदा कार्यक्रम होना था. पश्चिम बस्तर डिवीजन से आए प्रतिनिधि कॉमरेड बाबू ने शहीद वेदी का अनावरण कर वर्ष 2000 में सम्पन्न तीसरे अधिवेशन के बाद से इस अधिवेशन तक शहीद हुए तमाम कॉमरेडों को श्रद्धांजली पेश की. खासकर जून 2005 से 'सलवा जुडुम' के नाम पर जारी पाशविक एवं फासीवादी अभियान के दौरान निर्मम तरीके से मारे गए सैकड़ों लोगों की याद में वहां उपस्थित सभी कॉमरेडों की मुट्ठियां भिंच गईं. सभी कॉमरेडों ने आंखों में आंसुओं को दबाते हुए शहीदों के अधूरे सपनों को साकार बनाने का संकल्प लिया. इस कार्यक्रम के बाद तमाम प्रतिनिधियों ने अधिवेशन हाल में प्रवेश किया, जिसका नाम 'वीर शहीद कॉमरेड्स रवि, माधव, श्रीधर, मंगतू, विकास हाल' रखा गया था.हाल में सचिव कॉमरेड कोसा ने डीके एसजेडसी की तरफ से सभी प्रतिनिधियों का स्वागत कर सदन से सभी का परिचय कराया. एसजेडसी सदस्यों ने सभी प्रतिनिधियों को बैज पहनाया.

सबसे पहले सदन ने अधिवेशन के संचालन के लिए एक अध्यक्षमण्डल का चुनाव किया. निवृत्तमान एसजेडसी ने स्टीयरिंग (संचालन) कमेटी के रूप में काम किया. उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजली पेश करते हुए एक प्रस्ताव और जेल बन्दियों को संदेश का प्रस्ताव पेश किया गया, जिन्हें सदन ने एकमत से पारित किया. उसके बाद केन्द्रीय कमेटी के एक कॉमरेड ने उद्घाटन भाषण दिया. उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आज दण्डकारण्य समेत देश भर में क्रान्ति प्रति-क्रान्ति का सामना कर रही है. दण्डकारण्य में प्राथमिक रूप में आकार ले रही जनता की नई जनसत्ता को देखकर प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग भय से कांप रहे हैं. इसीलिए वे सलवा जुडुम जैसे बर्बरतापूर्ण अभियानों के जरिए इसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका अमेरिकी साम्राज्यवादी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं. देश-दुनिया के वर्तमान हालात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि आज अमेरिकी साम्राज्यवाद अलग-थलग पड़ चुका है. विश्व भर में जनता साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के खिलाफ संघर्ष कर रही है.

यह अधिवेशन कुल 14 दिनों तक चलता रहा. अधिवेशन में पार्टी के बुनियादी दस्तावेज -- मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के चमकते लाल झण्डे को ऊंचा उठाए रखो, पार्टी संविधान, पार्टी कार्यक्रम, भारतीय क्रान्ति की रणनीति-कार्यनीति और देशीय-अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर राजनीतिक प्रस्ताव -- पेश किए गए. इसके अलावा पुरानी भाकपा (माले) (पीडब्ल्यू) एवं पुरानी एमसीसीआई की राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षाओं और पुरानी पीडब्ल्यू की 2001 से 2004 तक की समीक्षा पर बहस हुई. सबसे पहले मा-ले-मा दस्तावेज पर बहस हुई. माओवाद को मार्क्सवाद का 'पूर्णतः' नया एवं उन्नत मंजिल के रूप में लिखे जाने के संदर्भ में 'पूर्णतः' शब्द को हटाने को लेकर मत-विभाजन हुआ. बहुमत ने हटाने के पक्ष में वोट दिया. कुछ साथियों ने अपना यह मत बड़ी गहराई से पेश किया कि मा-ले-मा एक दर्शन है और विज्ञान है. निरन्तर विकसित

होने वाले सिद्धान्त को एक दस्तावेज के रूप में रखना सही नहीं है, बल्कि इसे एक अध्ययन नोट्स के रूप में रखा जाना चाहिए. लेकिन चर्चा के बाद सदन भारी बहुमत के साथ इस तर्क को खारिज कर दिया और मा-ले-मा को पार्टी के बुनियादी दस्तावेज के रूप में रखने को सही ठहराया. बाद में इस दस्तावेज को एकमत के साथ पारित किया गया. इसी क्रम में पार्टी संविधान और पार्टी कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई और कुछेक संशोधनों के साथ एकमत के साथ पारित किया गया. पार्टी कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान 'युग के सवाल' पर मत विभाजन हुआ. बहुमत ने यह माना कि यह युग अभी भी 'साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्तियों का युग' है, जैसा कि लेनिन ने परिभाषित किया. सबसे रोचक और जीवन्त बहस-मुबाहिसा 'भारतीय क्रान्ति की रणनीति-कार्यनीति' दस्तावेज पर चला. इसमें मौजूद कई बिन्दुओं पर मत-विभाजन हुआ. चुनाव बहिष्कार को रणनीतिक महत्व वाला मुद्दा न मानकर कार्यनीतिगत मुद्दा माना जाना चाहिए, ऐसा कुछ कॉमरेडों ने वितर्क रखा. लेकिन सदन ने बहुमत के साथ इसे खारिज करते हुए दस्तावेज को सही ठहराया. उसके बाद भारत के दलाल नौकरशाह पूंजीपति की भूमिका एवं चरित्र को लेकर रोचक बहस हुई. मत-विभाजन के बाद बहुमत ने माना कि 'भारत में साम्राज्यवादी शोषण के लिए दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग दोनों ही मुख्य वाहक के रूप में बने हुए हैं' तथा 'भारतीय राज्य बड़े पूंजीपतियों एवं बड़े जमींदारों की सांझी तानाशाही है'. इसके बाद सदन ने इस दस्तावेज को कुछ संशोधनों के साथ एकमत से पारित किया.

बाद में दोनों भूतपूर्व (पुरानी) पार्टियों की राजनीतिक-सांगठनिक समीक्षाओं (पीओआर) को चर्चा में लिया गया. इस दौरान पुरानी एमसीसीआई और पुरानी भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) की एकता-प्रक्रिया के मुद्दों एवं काले अध्याय के बारे में घटनाओं का विवरण देते हुए दोनों पुरानी पार्टियों के केन्द्रीय कमेटी कॉमरेडों ने अपनी-अपनी आत्मालोचना बड़ी गहराई से पेश की. पूरा अधिवेशन हाल भावुक हो उठा. दोनों पार्टियों की एकता में हुए दशकों के विलम्ब को लेकर भी कुछ प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए. पूरे सदन ने भारतीय क्रान्ति के हित में दोनों पार्टियों की एकता की आवश्यकता और महत्व को दिल से महसूस किया. इन दस्तावेजों को कुछ संशोधनों के साथ पारित किया गया. दण्डकारण्य की पीओआर पर प्रतिनिधियों ने गहन चर्चा व बहस की क्योंकि यह उनके ही कामकाज और कार्यक्षेत्र जुड़ा हुआ रिपोर्ट दस्तावेज था. इस पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिनिधियों ने बड़ी प्रमुखता से यह बात सामने लाई कि नेतृत्व के कामकाज के तरीके में अभी भी स्वतःस्फूर्तता काफी बड़े पैमाने पर मौजूद है जो दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन को आगे ले जाने में एक बाधक है. बराबर मत-विभाजन के बाद स्टीयरिंग कमेटी ने इसे मान लिया और इसे एक प्रमुख कमजोरी के रूप में चिन्हित किया. बहस बहुत संजीदगी एवं तीखे रूप से चली जिससे डीके पीओआर और भी समृद्ध हुआ तथा आगे का कार्यभार तय करने में बहुत मददगार साबित हुआ. इस दस्तावेज में दण्डकारण्य के आन्दोलन में आए नए मोड़ को अधिवेशन ने पहचाना और इसे अधिवेशन ने इस आन्दोलन की एक मुख्य उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया.

सारे दस्तावेजों को पारित करने के बाद आत्मालोचना-आलोचना की बारी थी. पिछले 6 सालों के व्यवहार में हुई गलतियों एवं खामियों को चिन्हित करते हुए सबसे पहले केन्द्रीय कमेटी सदस्यों और बाद में डीके एसजेडसी सदस्यों ने अपनी आत्मालोचना पेश की. बाद में प्रतिनिधियों ने नेतृत्व में मौजूद कमजोरियों के बारे में तीखी व स्पष्ट आलोचना अधिवेशन के सामने रखी, जिसे डीके एसजेडसी के साथियों ने मान लिया और उन्हें दूर करने की कोशिश को जारी रखने का भरोसा दिलाया. उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी ने नई एसजेडसी के चुनाव के लिए एक पैनल पेश किया. चर्चा के बाद इस पैनल को अधिवेशन ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया. नव निर्वाचित एसजेडसी ने कॉमरेड कोसा को फिर से अपना सचिव चुन लिया. बाद में नव निर्वाचित एसजेडसी ने शपथ-ग्रहण किया और दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने हेतु भरसक कोशिश करने का भरोसा दिलाया. इस अधिवेशन में भाग लेने वाले केन्द्रीय कमेटी सदस्यों ने न सिर्फ इसका मार्गदर्शन किया, बल्कि विभिन्न अवसरों पर दिए गए अपने भाषणों एवं वक्तव्यों से अधिवेशन को गरिमामय बनाया. उनके प्रत्यक्ष निर्देशन में दण्डकारण्य स्पेशल जोन का चौथा अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ.

इस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने पार्टी में विवादित रहे कई राजनीतिक मुद्दों पर भाग लेते हुए गहराई और परिपक्वता का परिचय दिया. इस अधिवेशन के लिए पार्टी, पीएलजीए, जनतना सरकार, जन संगठन और विभिन्न तकनीकी विभागों से प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था. भीषण शत्रु दमन के बीचोबीच सम्पन्न डिवीजन अधिवेशनों में जोन अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था. इसके अलावा विभिन्न राज्यों एवं विभागों में काम करने वाले कुछ कॉमरेडों ने इस अधिवेशन में पर्यवेक्षकों के रूप में भी भाग लिया. 14 दिनों तक चले दण्डकारण्य अधिवेशन के बाद सभी प्रतिनिधि नए नारों,नए कार्यभारों और नए उत्साह के साथ अपने-अपने कार्यक्षेत्रों की ओर लौट चले. ✶

खेद है !

- **'प्रभात' के जनवरी-मार्च 2006 अंक के बाद से लगभग एक साल तक 'प्रभात' का प्रकाशन नहीं हो सका. इस असुविधा के लिए हमें खेद है. कुछ अनिवार्य कारणों से लगातार 3 अंक छूट गए. हमारी कोशिश रहेगी कि 'प्रभात' का नियमित रूप से प्रकाशन हो.**
- **इस वर्ष 'प्रभात' के 20 बरस पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर हम अगले अंक में एक विशेष लेख प्रकाशित करने की कोशश करेंगे.**
- **पिछले एक साल के दौरान दण्डकारण्य आन्दोलन में कई कॉमरेड शहीद हुए हैं. इनमें से कई कॉमरेडों की जीवनियां और तस्वीरें हम इकट्ठी नहीं कर पाए. पाठकों से हमारा विनम्र अपील है कि जिन-जिन शहीदों की जीवनियों का 'प्रभात' में प्रकाशन नहीं हो पाया है, उन्हें लिख भेजिए.**
- **पाठकों से अपील है कि 'प्रभात' के लिए रिपोर्टें नियमित रूप से भेजते रहें. आपकी आलोचनाओं और टिप्पणियों का इंतजार तो हमें हमेशा ही रहेगा.**

- सम्पादक मण्डल

सैद्धांतिक लेख

संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष किये बिना क्रान्ति के लिए एक कदम भी आगे बढ़ना सम्भव नहीं

1. विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में 1956 में ख्रुश्चोव संशोधनवाद का उद्‌भव और उसके खिलाफ चला आ रहा तीखा संघर्ष का इतिहास आज करीब पचास वर्ष पार कर चुका है। पर आज भी संशोधनवाद विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन के सामने मुख्य खतरा बना हुआ है। इसलिए सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक व कार्यपद्धति के क्षेत्र में संशोधनवाद के खिलाफ लगातार संघर्ष का संचालन करना व उसके साथ साफ विभाजन रेखा खींचना तथा उसे पराजीत करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। विगत 150 वर्षों से चला आ रहा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास और खासकर पेरिस कम्यून, रूसी क्रान्ति, चीनी क्रान्ति आदि के इतिहास ने हमें यही शिक्षा दी है कि संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष किये बिना हम क्रान्ति के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह एक सर्वजनीन सच्चाई है।

2. दरअसल, मार्क्सवाद के जन्म के साथ ही उसके विपरीत सिद्धान्त के बतौर संशोधनवाद व संशोधनवादी विचार तथा संशोधनवादी कार्यधारा सामने आयी है। महान मार्क्स के जीवित रहने के समय में ही मार्क्स और एंगेल्स ने विरोधी मतों के रूप में मौजूद हेगेल के भाववाद सहित प्रूद्धोंवाद व बकूनिनवाद आदि को परास्त किया था। उस समय उन सभी विचारों को विरोधी मतों के बतौर ही चिन्हित किया गया, संशोधनवाद के रूप में नहीं। पर, बर्नस्टीन ने ही व्यापक शोर मचाकर मार्क्सवाद का संशोधन किया, मार्क्सवाद पर पुनर्विचार किया और उन्होंने जिस विचारधारा को अधिकतम अविकल अभिव्यक्ति के रूप में सामने लाया इस प्रवृति को ही संशोधनवाद के रूप में चिन्हित किया गया। वस्तुत:, राजनीति के क्षेत्र में संशोधनवाद ने मार्क्सवाद के आधार यानी वर्ग संघर्ष की शिक्षा और वर्ग संघर्ष के जरिए पूंजीवाद का खात्मा कर समाजवाद की स्थापना की जरूरत को ही तिलांजलि दे डाली।

जाहिर है कि संशोधनवाद एक अन्तरराष्ट्रीय परिघटना है। 'अन्तिम लक्ष्य कुछ नहीं, आन्दोलन ही सब कुछ है'- यह उक्ति संशोधनवाद के सार की ही अभिव्यक्ति है।

3. का. लेनिन ने कहा था, "19वीं सदी के अन्त में संशोधनवाद के खिलाफ क्रान्तिकारी मार्क्सवाद का वैचारिक संघर्ष सर्वहारा वर्ग की जो टुटपूंजिया वर्ग की सारी ढुलमुल यकीनियों और कमजोरियों के बावजूद अपने हेतु की पूर्ण विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। महान क्रान्तिकारी लड़ाइयों की केवल भूमिका है।" (मार्क्सवाद और संशोधनवाद- लेनिन)

1917 में महान लेनिन की रहनुमाई में रूस देश में महान अक्टूबर रूसी समाजवादी क्रान्ति ने अपनी सफलता हासिल की। तब मार्क्सवाद की जड़ और मजबूत हुई। कारण, इतने दिनों तक मार्क्सवाद केवल किताब के पन्नों पर ही लिखा हुआ था। पर रूसी क्रान्ति ने उस मार्क्सवाद की बुनियादी बातों को यानी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था को दुनिया के एक हिस्से से उखाड़ फेंककर एक नयी व्यवस्था मजदूर-किसान की व्यवस्था यानी समाजवादी समाज का जन्म दिया।

वस्तुत:, रूसी क्रान्ति की अग्रगति के हर चरणों में का. लेनिन को अन्तरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर घोर संशोधनवादी प्लेखानोव, काउत्स्की से शुरू कर मारतोव, ट्रटस्की सहित तमाम मेनशेविकों के खिलाफ जोरदार संघर्ष चलाना पड़ा था और उन संशोधनवादी व क्रान्ति-विरोधी विचारों को परास्त करना पड़ा था। तभी, केवल तभी रूसी क्रान्ति सफल हो पायी।

जाहिर है कि पूंजीवाद से उसकी चरम अवस्था साम्राज्यवाद के बारे में तथा साम्राज्यवाद के स्तर में ही पूंजीवाद के तमाम अन्तरविरोधों का काफी तीखा व तीव्र हो जाने के कारण क्रान्ति की फौरी संभावना के बारे में का. लेनिन ने ही व्याख्या-विश्लेषण प्रस्तुत किया। का. लेनिन ने अक्सर साम्राज्यवाद के स्तर को क्रान्ति के पूर्वबेला के रूप में चिन्हित किया। साम्राज्यवाद व साम्राज्यवादी युद्ध की स्थिति में सर्वहारा वर्ग तथा उसकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का कर्तव्य क्या है– इस प्रश्न को लेकर दूसरा इण्टरनेशनल के बर्नस्टीन, काउत्स्की आदि घोर संशोधनवादी नेताओं के खिलाफ तीव्र वैचारिक संघर्ष चलाने के साथ-साथ रूसी पार्टी के अन्दर के संशोधनवादियों के खिलाफ भी का. लेनिन और का. स्तालिन को तीव्र संघर्ष चलाना पड़ा। साम्राज्यवादी युद्ध के समय अपनी पितृभूमि की रक्षा करनी चाहिए– गद्दार काउत्स्की के इस विचार के खिलाफ साम्राज्यवादी युद्ध को गृहयुद्ध में बदल डालो यानी देश-देश में सर्वहारा वर्ग की पार्टी द्वारा वहाँ की क्रान्ति को सफल बनाओ– महान लेनिन द्वारा स्थापित इस सुप्रसिद्ध प्रस्थापना के जरिए कम्युनिस्टों के सही कर्तव्य को सामने लाकर एक तीखा संघर्ष चलाया गया तथा काउत्स्की के घोर संशोधनवादी सिद्धान्त को परास्त किया गया। इस सिद्धान्त के धाराप्रवाह में ही अंतत: महान लेनिन-स्तालिन के नेतृत्व में संशोधनवादियों की तमाम साजिशों को चकनाचूर कर महान रूसी क्रान्ति सफल हुई। इसी धारा-प्रक्रिया के दौर में ही मार्क्सवाद विकसित होकर उसका दूसरा विकसित स्तर लेनिनवाद के स्तर में पहुंच गया। संशोधनवाद के विरूद्ध तीखा व तीव्र संघर्ष चलाने और वर्ग संघर्ष को मूल आधार मानते हुए तथा साम्राज्यवाद के स्तर में क्रान्तिकारी वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए रूसी क्रान्ति को सफल बनाने के क्रम में ही सिद्धान्त को और धारदार बनाने की जरूरत हुई और मार्क्सवाद का लेनिनवाद में विकास होकर ही यह जरूरत पूरी हुई।

4. महान लेनिन की मृत्यु के बाद, सोवियत रूस में समाजवादी निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के क्रम में का. स्तालिन को हर कदम पर संशोधनवादियों और षड्‌यंत्रकारियों के विरूद्ध जोरदार संघर्ष करना पड़ा। खासकर ट्रटस्की, जिनोवियेव, बुखारिन आदि घनघोर संशोधनवादी, षड्‌यंत्रकारियों के हर प्रतिक्रान्तिकारी कदम का मुकाबला करके ही समाजवाद व समाजवादी निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना पड़ा।

5. 1953 में महान स्तालिन की मृत्यु हुई। इसके बाद ही

इतने दिनों तक पार्टी के अन्दर कुण्डली मारकर बैठे हुए ख्रुश्चोव ने अपना असली चेहरा लेकर सामने आया। 1956 में बीसवीं कांग्रेस के जरिए ही ख्रुश्चोव द्वारा पेश किया गया 'शान्तिपूर्ण संक्रमण', 'शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता', 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व' और बाद में 'सम्पूर्ण जनता का राष्ट्र' के सिद्धान्तों के फलस्वरूप ही ख्रुश्चोव संशोध नवाद का एक सुसम्बद्ध लाइन के रूप में आविर्भाव हुआ। इस ख्रुश्चोव संशोधनवाद को ही पुराने समय के संशोधनवाद की जगह आधुनिक संशोधनवाद के रूप में चिन्हित किया गया। क्यों ऐसा किया गया? इसके दो बुनियादी कारण हैं :

(i) पुराने समय के संशोधनवाद और संशोधनवादियों के हाथ में कोई राजसत्ता नहीं थी। इसलिए उस समय सत्ता का इस्तेमाल ओर दुरूपयोग करने का कोई प्रश्न नहीं था। मूलत: विचारधारा के बतौर ही संशोधनवाद क्रान्ति-विरोधी भूमिका निभाता था।

(ii) परन्तु, ख्रुश्चोव संशोधनवाद का जन्म का. स्तालिन की मृत्यु के बाद महान लेनिन-स्तालिन द्वारा निर्मित सर्वहारा की एक शक्तिशाली समाजवादी समाज व्यवस्था और उससे सम्बन्धित राजसत्ता को अपने कब्जे में लाकर ही हुआ है। अत: सत्ता का इस्तेमाल करते हुए शान्तिपूर्ण रास्ते से समाजवाद में संक्रमण जैसे क्रान्ति-विरोध ी सिद्धान्त को एक रणनीतिक सिद्धान्त के रूप में लागू करने व करवाने के बारे में इसका प्रभाव जबरदस्त रहा।

मूलत: इन दो कारणों से ख्रुश्चोव संशोधनवाद को आधुनिक संशोधनवाद के रूप में चिन्हित किया गया।

वस्तुत: ख्रुश्चोव संशोधनवाद के उद्भव के बाद ही दुनिया के विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों के अन्दर सबसे ज्यादा फूट व विभाजन पैदा हुआ। खासकर शान्तिपूर्ण रास्ते से समाजवाद में जाने की संशोध नवादी नीति को तमाम संशोधनवादी पार्टी व उसके नेता लोग एक रणनीति के बतौर ग्रहण करते हुए चुनाव में हिस्सा लेने के कार्यक्रम को एकमात्र कार्यक्रम के रूप में ग्रहण किये। उनके द्वारा संचालित तमाम जन आन्दोलन व जन संगठन का लक्ष्य भी संसदीय धारा के अनुरूप एम.एल.ए., एम.पी. व मंत्री बनना मात्र रह गया।

भारत की अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व भी जो महान तेलंगना संघर्ष के साथ गद्दारी किया और 1952 से ही चुनाव में हिस्सा लेना शुरू किया और उसको ही एकमात्र काम बना लिया, ख्रुश्चोव संशोधनवाद उन्हें और अध:पतन की ओर खींचकर ले गया।

जो भी हो, साम्राज्यवाद खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ साठगांठ व षड्यंत्र के जरिए सोवियत सत्ता पर काबिज होकर और समाजवाद का मुखौटा व सत्ता का दुरूपयोग कर ख्रुश्चोव संशोध नवाद और अधिक आक्रामक हुआ है तथा देश-देश में इसके दलाल संशोधनवादी पार्टी और इसके नेता लोग भी पहले की अपेक्षा और मजबूती के साथ संशोधनवादी सिद्धान्त को अख्तियार किये तथा शान्तिपूर्ण रास्ते से समाजवाद में पहुंचने के राहगीर बन गये। मुँह में समाजवाद व व्यवहार में साम्राज्यवाद और सत्ता का इस्तेमाल इत्यादि के जरिए रूस का अध:पतन पहले एक सामाजिक साम्राज्यवादी यानी सामाजिक फासीवादी शक्ति और बाद में एक महाशक्ति के रूप में हुआ।

6. दूसरा विश्वयुद्ध और स्तालिन के नेतृत्व में रूसी लालफौज द्वारा चरम फासिस्ट हिटलर की नाजी वाहिनी को ध्वस्त कर ऐतिहासिक विजय लाभ तथा एक समाजवादी खेमे के उदय होने के बाद 1949 में महान माओ के नेतृत्व में और एक दुनिया हिला देनेवाली क्रान्ति यानी चीनी क्रान्ति दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिए सफल हुई। का. माओ प्रदर्शित दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन अब एशिया, अफ्रीका व लातिन अमेरिका की जनता की मुक्ति की एकमात्र सही लाइन के रूप में सामने आई। इस लाइन को स्थापित करने के लिए भी का. माओ को चीनी पार्टी के अन्दर छन-तू-श्यू, ली-ली सान, वाङ-मिङ इत्यादि दक्षिण व 'वाम' संशोधनवादियों के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा और इस तरह चीनी क्रान्ति को सफल बनाने के साथ-साथ संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष के झण्डे को माओ ने और बुलन्द किया।

अत: ख्रुश्चोव संशोधनवाद के अविर्भाव के बाद ख्रुश्चोव संशोध नवाद तथा आधुनिक संशोधनवाद के विरूद्ध का. माओ द्वारा चलाया गया सैद्धान्तिक व विचारधारात्मक संघर्ष को ही महान बहस (Great Debate) के बतौर जाना जाता है। यूं तो मार्क्सवाद के उद्‌भव के समय से ही उसके विपरीत विचार के बतौर संशोध नवाद के विरूद्ध संघर्ष चला आ रहा है। पर, ख्रुश्चोव संशोधनवाद के विरूद्ध चलायी गई महान बहस पहले के किसी भी समय की अपेक्षा सबसे ज्यादा तीव्र व सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण और संशोधनवाद के साथ साफ विभाजन रेखा खींचनेवाली एक निर्णायक बहस के रूप में साबित हुई।

इस महान बहस के परिणामस्वरूप अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवाद बनाम संशोधनवाद (जिसका अन्तरवस्तु या केन्द्रबिन्दू सशस्त्र संग्राम का मार्ग अथवा संसदीय मार्ग रहा) के बीच की तीखी लड़ाई शुरू हुई और एक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया के जरिए सच्चे व नकली कम्युनिस्टों के दो खेमा स्पष्ट रूप से सामने आये। महान माओ के नेतृत्व में सच्चे कम्युनिस्टों के खेमा और मजबूत हुआ तथा संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष और जोरदार हुआ। फलस्वरूप, एशिया, अफ्रीका व लातिन अमेरिका के कुछ देशों में जारी सशस्त्र संग्राम में और तेजी आयी।

बाद में, माओ के नेतृत्व में पूंजीवाद के राहगीर व चीनी ख्रुश्चोव लिऊ-शाओ-ची एण्ड कम्पनी की सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व व वर्ग संघर्ष की जरूरत को खारिज करने और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना करने की लाइन के खिलाफ एक जटिल व तीव्र संघर्ष चलाया गया। जिसको महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के रूप में हम जानते हैं।

इसी तरह चीनी क्रान्ति के ठोस व्यवहार तथा अन्तरराष्ट्रीय वर्ग संघर्ष में उचित योगदान और मार्क्सवाद-लेनिनवाद की विभिन्न शाखाओं में अभूतपूर्व योगदान इत्यादि के जरिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद को माओ ने और विकसित किया जो माओ विचारधारा (अब माओवाद) तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विकास का तीसरा व गुणात्मक स्तर के रूप में सामने आया।

भारत में भी इसी समय अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर वितर्क काफी तीखा हुआ। खासकर 1962 में प्रतिक्रियावादी भारत सरकार द्वारा तत्कालीन समाजवादी चीन पर आक्रमण करने की घटना के बाद पार्टी के अन्दर आन्तरिक संघर्ष और तीखा व तीव्र हुआ। महान बहस, दुनिया हिला देनेवाली महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति और नक्सलबाड़ी के महान किसान विद्रोह, इन युगान्तकारी घटनाओं के परिणामस्वरूप भारत में भी संशोधनवादी खेमा और कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी खेमा साफ तौर पर उजागर हुआ।

7. परन्तु का. स्तालिन की मृत्यु के बाद गद्दार ख्रुश्चोव द्वारा

पार्टी व सत्ता पर काबिज हो जाना और सर्वहारा अधिनायकत्व के बदले बुर्जुआ अधिनायकत्व का कायम हो जाना– इसी तरह से महान लेनिन, स्तालिन के नेतृत्व में स्थापित पहली समाजवादी पितृभूमि का अन्त हो गया। फिर, का. माओ की मृत्यु के तुरन्त बाद ही, चार क्रान्तिकारी कामरेडों को 'चार गुट' के नाम से चिन्हित कर एक प्रतिक्रान्तिकारी राज्य विप्लव (या कूदेता) के जरिए तेङ-हुआ गुट ने समाजवादी चीन का रंग बदल दिया और चीन में भी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के स्थान पर बुर्जुआ अधिनायकत्व कायम हुआ। इसी तरह महान माओ और उनकी रहनुमाई में सी.पी.सी. द्वारा स्थापित समाजवाद का एक शक्तिशाली किला का भी अन्त हो गया। अब दुनिया के किसी भी देश में एक समाज व्यवस्था के रूप में समाजवाद का अस्तित्व नहीं रह गया। पार्टी के अन्दर छिपे संशोधनवादी व प्रतिक्रियाशील शक्ति द्वारा मौके पर पार्टी व सत्ता पर जोर जबरन कब्जा जमाना और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना करना, यही मूल कारण रहा जिससे सर्वहारा वर्ग व समाजवाद का अस्थायी तौर पर ही सही, पराजय हाथ लगा।

अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की इन नकारात्मक घटनाओं के फलस्वरूप संशोधनवाद और संशोधनवादी सोच, कार्यशैली व रीति-रिवाजों का भी पुन: सिर उठाकर अपना प्रभाव जमाने का मौका मिला। खासकर, गद्दार तेङ गुट द्वारा समाजवादी चीन का रंग बदल दिये जाने के बाद अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन और एक विभाजन की प्रक्रिया के दौर से गुजरा और इसी तरह से यह आन्दोलन काफी धक्का खाया।

8. परन्तु अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में आया धक्का अथवा संशोधनवाद का हावी होना, इत्यादि एक भी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार एकदम अन्तिम (absolute) बात नहीं है, बल्कि सापेक्ष (relative) है। अत: धक्का को पुन: अग्रगति में और संशोधनवाद की हावी होने की स्थिति को पीछे धकेल कर मार्क्सवाद को पुन: प्रभावशाली बनाने की स्थिति में बदल दिया जा सकता है, बशर्ते कि हम द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी नियमों पर दृढ़ विश्वास रखें और आज की वस्तुस्थिति के अनुसार उसे अमल में लायें तथा सशस्त्र संघर्ष या दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन पर अडिग रहें व मजदूर-किसान, मेहनतकश जनता पर पूर्ण भरोसा रखें और हर काम में उनको शामिल करें। दुनिया में सबकुछ ही दो विपरीत चीज की एकता के नियम के अनुसार अस्तित्वमान है। जिसमें संघर्ष का पहलू स्थायी व निरपेक्ष और एकता का पहलू अस्थायी व सापेक्ष होता है। इसलिए खराब को अच्छा में बदलना, प्रतिकूल को अनुकूल में बदलना ये सबकुछ ही संभव है।

9. संशोधनवाद प्रधान खतरा है– इस बात को बहुत लोग कथनी में तो मान लेते हैं, पर करनी में, संशोधनवाद प्रधान खतरा है और इसीलिए व्यवहार के क्षेत्र में या कार्य पद्धति के क्षेत्र में भी संशोधनवादी कार्य पद्धति व तौर-तरीकों के साथ सुस्पष्ट सीमारेखा खींचने की आवश्यकता है- इसे अमल में लाने में अक्षम रह जाते हैं। परिणामत: संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष अपूर्ण या अधूरा रह जाता है। इसलिए संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष को, कथनी व करनी दोनों तरीकों से, गहराई से व बेहिचक ढंग से और शुरू से अन्त तक लगातार चलाने की जरूरत है। किसी भी कारणवश संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष में ढिलाई बरतने का मतलब ही होगा संशोधनवाद को और टिकाकर रखने में मदद करना।

10. संशोधनवाद कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। संशोधनवाद लगातार पैंतरा बदलते रहता है। मार्क्स के समय में संशोधनवाद जिस रूप में सामने आया अथवा लेनिन, स्तालिन के समय में संशोधनवाद जिस रूप से उजागर हुआ, आज के समय में संशोधनवाद उससे भिन्न रूप में सामने आया है तथा भविष्य में भी दूसरे नये रूपों में सामने आएगा। लाल झण्डा लेकर लाल झण्डा का विरोध करना, क्रान्ति का नाम लेकर क्रान्ति का विरोध करना, मार्क्सवाद-लेनिनवाद का नाम लेकर मार्क्सवाद-लेनिनवाद का विरोध करना, माओ विचारधारा का नाम लेकर माओ विचारधारा का विरोध करना या माओवाद का नाम लेकर माओवाद का विरोध करना– यही संशोधनवाद का मौजूदा स्वरूप है। इसे अत्याधुनिक संशोधनवाद भी कहा जाता है।

अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति का परस्पर विरोधी व अब क्रान्ति होने की स्थिति नहीं है जैसा निराशाभरा विश्लेषण करना और माओवाद का ऐतिहासिक व अन्तरराष्ट्रीय महत्व को नकारना तथा नयी परिस्थिति, ठोस विश्लेषण, शक्ति संतुलन आदि सवालों को सामने लाकर असल में अभी 'सशस्त्र क्रान्ति की स्थिति नहीं है', इस विश्लेषण को रखकर घुमा-फिराकर संसदीय मार्ग का वकालत व अख्तियार करना– यही अत्याधुनिक संशोधनवाद की विशेषताएं हैं।

11. भारत में भी, तेलंगना आन्दोलन के साथ खुल्लम-खुला बेईमानी करनेवाले अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोगों ने बहुत पहले ही सशस्त्र संग्राम को परित्याग कर संसदीय मार्ग अपना लिया और तब से संशोधनवादियों का एकमात्र काम रहा संसदीय मार्ग का तारीफ करना और चुनाव में हिस्सा लेकर एम.एल.ए., एम.पी. व मंत्री बनना तथा हर संभव तरीके से क्रान्ति का विरोध करना और इस तरह शोषक-शासक गुटों की सेवा करना। पर, 1967 में महान नक्सलबाड़ी के किसान विद्रोह फूट पड़ने के बाद उसके खिलाफ नंगा आक्रमण चलाने के फलस्वरूप सी.पी.एम. नेताओं का चरम क्रान्ति-विरोधी चरित्र का भण्डाफोड़ हो गया और इस तरह इन गद्दार व नया संशोधनवादी सी.पी.आई.(एम) आदि के साथ क्रान्तिकारी खेमा का एक सुस्पष्ट विभाजन हो गया। संशोधनवाद आज साम्राज्यवाद के लिए इतना ही प्यारा हो गया है कि पिछले 30 वर्षों से पश्चिमी बंगाल में संशोधनवादियों के सरगना सी.पी.आई.(एम) के नेतृत्वाधीन वामफ्रण्ट सरकार सभी जनवादी व क्रान्तिकारी ताकतों को सामाजिक फासीवादी तरीकों से दमन कर अपना राज चला रही है और साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीपति व सामंतवाद का विश्वस्त दलाल की भूमिका निभा रही है। विगत 30 वर्षों के दौरान राजसत्ता का इस्तेमाल व दुरूपयोग करते हुए सी.पी.आई.(एम) ने अपने पार्टी के समूचे स्तरों को एक जबरदस्त सामाजिक फासीवादी शक्ति के बतौर तैयार किया जो मार्क्सवाद का मुखौटा धारण कर व लाल झण्डा हाथ में लेकर एक संगठित प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति की भूमिका निभा रही है। स्थिति ऐसी है कि भारत के कुछ प्रान्तों में सी.पी.आई.(एम) के फासीवादी आक्रमण का मुकाबला किये बिना जनवादी व क्रान्तिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाना नामुमकीन है।

फिर, 1972 में का. सी.एम. की शहादत के बाद, सत्यनारायण सिंह जैसे कुछ लोगों द्वारा 'वाम' लाइन सुधारने के नाम पर चुनाव में हिस्सा लेने की दक्षिणपंथी लाइन व कार्यधारा अपनाया गया। इसके अलावे माओ विचारधारा का नाम जपने वाले सी.पी.आई.

(एम-एल) लिबरेशन व कानु सन्याल के नेतृत्वाधीन एक एम-एल पार्टी भी बहुत पहले ही सशस्त्र संघर्ष का मार्ग परित्याग करते हुए संसदीय रास्ते का भक्त बन गयी और मौजूदा जालसाजीपूर्ण चुनाव के खेल में हिस्सा लेकर आत्मसमर्पण के बदले शोषक वर्ग का जूठन के बतौर संसद, विधानसभा व पंचायत चुनाव में दो या चार सीट पाने के लिये कूद पड़ी है। वर्ग युद्ध के मैदान में क्रान्ति-विरोध ी भूमिका निभाना यानी क्रान्तिकारी संघर्ष के खिलाफ दुष्प्रचार करना, क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाना व ऐसा कि हत्या करना– ये सब कुछ ही लिबरेशन द्वारा चलाये जा रहे कुकर्मों के नमूने हैं और अध:पतित कानु सन्याल तो शोषक-शासकों का इतना प्यारा आदमी बन गया है कि सी.पी.आई.(माओवादी) के खिलाफ और हिंसा से कतई जनता की भलाई या क्रान्ति नहीं हो सकती जैसा उनका ब्यान को केन्द्र या राज्य सरकारें मिलकर तथा उसके पुलिस विभाग द्वारा हजारों-हजार प्रतियां छापकर वितरण किया जा रहा है। झारखण्ड व बिहार में पुलिस-प्रशासन द्वारा वितरण किया गया वैसा ब्यान इसकी जीती-जागती मिसालें हैं।

इन रूपों के संशोधनवाद द्वारा चलाया जा रहा सशस्त्र हमले का मुकाबला किये बिना क्रान्तिकारी संघर्षों को आगे बढ़ाना करीब नामुमकीन है। देश-विदेश के क्रान्तिकारी इतिहास भी हमें यही शिक्षा देता है।

12. जब से मजदूर वर्ग के आन्दोलन का उद्भव हुआ, तब से ही बुर्जुआ वर्ग मजदूर वर्ग को सैद्धान्तिक व विचारधारात्मक रूप से भ्रष्ट बनाने की कोशिश में संलग्न है ताकि मजदूर आन्दोलन को बुर्जुआ वर्ग के मूल स्वार्थ के अधीन रखा जा सके तथा समूचे देशों की जनता के क्रान्तिकारी संघर्षों को कमजोर व गुमराह किया जा सके। इस मकसद से बुर्जुआ विचारधारात्मक रूझान विभिन्न समय में विभिन्न रूप धारण कर लेता है, कभी दक्षिणपंथी तो कभी 'वाम' भटकाववादी रूप लेते रहते हैं। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के उद्भव व विकास का इतिहास भी बुर्जुआ विचारधारा के रूझानों के खिलाफ चाहे वह दक्षिणपंथी रूझान हो या 'वाम', उसके खिलाफ तीखा संघर्ष का इतिहास है। सच्चे मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादियों का कर्तव्य है कि बुर्जुआ विचारधारात्मक रूझान द्वारा पेश की गई चुनौती का सामना करने से भागना अथवा डरना नहीं, बल्कि महान मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्तालिन व माओ ने जैसे किये वैसा करना यानी जब भी बुर्जुआ विचार तथा संशोधनवादी विचार द्वारा सिद्धान्त, मौलिक लाइन व नीति के क्षेत्र में आक्रमण होगा, तभी उस आक्रमण को ध्वस्त कर देना और सर्वहारा वर्ग, उत्पीड़ित जनता व जातियों द्वारा चलाया जा रहा संघर्षों के विजय मार्ग को सुनिश्चित करना। मार्क्सवाद बनाम संशोधनवाद के संघर्ष का लम्बा इतिहास हमें दिखलाता है कि कुछ कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी तो अन्तर्वस्तु व रूप, दोनों में ही पूरे के पूरे संशोधनवादी बन गई है। जैसे इटली, फ्रांस आदि यूरोप की कुछ जाने-पहचाने पार्टियां और भारत में सी.पी.आई., सी. पी.आई.(एम) आदि पार्टियां। कुछ पार्टियों का तो सामाजिक फासीवादी शक्ति के रूप में अध:पतन हो चुका है तथा कुछ पार्टियां और ज्यादा संशोधनवादी लाइन व कार्यधारा अपनाने पर आमादा हो चुकी हैं और कुछ बीच में डोल खा रही हैं।

पर, सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर भी मार्क्सवाद के विपरीत विचार के बतौर संशोधनवाद तथा बुर्जुआ व पेटी-बुर्जुआ रूझान मौजूद रहता है। हमारे अन्दर भी संशोधनवाद मौजूद है। यद्यपि कि हमारे अन्दर प्रधान रूप से नहीं, फिर भी कुछ ठोस बहि:प्रकाश (manifestations) के रूप में संशोधनवाद तथा बुर्जुआ व पेटी-बुर्जुआ विचार मौजूद रहता है। खासकर अर्थवाद, जुझारू अर्थवाद, कानूनवाद, स्वत:स्फूर्तता आदि विभिन्न ठोस रूपों की अभिव्यक्ति हमारे अन्दर, हमारी पार्टी के अन्दर है। फिर हमारे अन्दर संकीर्णतावाद, मनोगतवाद व कठमुल्लावाद की अभिव्यक्ति तथा नम्रता व विनय का अभाव दिखलाई पड़ती है। इसके अलावे पूर्वाग्रह, व्यक्तिवाद, नौकरशाही प्रवृति व अहंवाद– ये भी हमारे अन्दर प्रचूर मात्रा में मौजूद हैं, जिससे कि हमारी नवगठित पार्टी के अन्दर की एकरूपता को और मजबूत करने में कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं।

दरअसल हमारे अन्दर मार्क्सवाद और संशोधनवाद दोनों ही मौजूद है। फिर संशोधनवाद कहने से उसके दोनों स्वरूप, दक्षिणपंथी अवसरवाद व 'वाम' भटकाववाद दोनों मौजूद हैं। यद्यपि प्रधान पहलू मार्क्सवाद ही है, फिर भी गौण पहलू के रूप में संशोधनवादी अभिव्यक्तियां भी मौजूद हैं। इसलिए एक ओर वास्तविक वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध में हिस्सा लेकर खुद को और फौलादी बनाना और दूसरी ओर खुद के अन्दर की संशोधनवादी अभिव्यक्तियों के खिलाफ भी संघर्ष चलाना निहायत जरूरी है। और इस प्रक्रिया को केवल थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि निरन्तर चलाना चाहिए। हमें का. लेनिन की इस बात कि ''राजसत्ता का सवाल ही तमाम क्रान्तियों का बुनियादी सवाल है'' और वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाकर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को स्थापित करना ही हमारा कर्तव्य है तथा साथ-साथ हमें माओ की इस महत्वपूर्ण उक्ति कि ''सशस्त्र बल द्वारा राजसत्ता छीनना, युद्ध द्वारा मसले को सुलझाना, क्रान्ति का केन्द्रीय कार्य और सर्वोच्च रूप है''– पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए। साथ-साथ संशोधनवाद नहीं मार्क्सवाद अमल करो; षड्यंत्र नहीं, खुले हृदय का हो जाओ; और विभक्त नहीं, एकताबद्ध हो जाओ- को अपने क्रान्तिकारी व्यावहारिक जीवन में अमल करने की कोशिश करनी चाहिए।

13. हमारे पार्टी के संस्थापक नेता व शिक्षक का. सी.एम. और का. के.सी. भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन में सी.पी.आई., सी. पी.आई.(एम) मार्का संशोधनवाद के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष करके तथा उसके साथ सुस्पष्ट विभाजन रेखा खींचते हुए ही भारत में माओ प्रदर्शित दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन को स्थापित करने में समर्थ हुए थे। उस संघर्ष की धारावाहिकता में ही उसका व्यावहारिक प्रतिबिम्ब के बतौर का. सी.एम. के नेतृत्व में महान नक्सलबाड़ी किसान आन्दोलन का उभार हुआ जो संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष में 'बसंत का बज्रघोष' साबित हुआ। संशोधनवाद के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाता है तथा उसे नेस्तानाबूद किया जाता है- हमारे शिक्षक का. सी.एम. व का. के.सी. से हमें हर पल शिक्षा लेनी चाहिए तथा इसका दृढ़तापूर्वक अनुसरण करना चाहिए।

आवें, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद के सिद्धान्त पर अडिग रहें; क्रान्तिकारी वर्ग संघर्ष व जारी कृषि क्रान्तिकारी छापामार लड़ाई में और सृजनशीलता के साथ व सक्रियतापूर्वक तथा बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। फौज व आधार इलाका निर्माण के कार्य को तेज करें। संशोधनवाद तथा संशोधनवाद के हर ठोस बहि:प्रकाश के विरूद्ध कथनी व करनी में निरन्तर संघर्ष चलाएं। याद रखें कि संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष किये बिना क्रान्ति के लिए एक कदम भी आगे बढ़ना संभव नहीं। ✶

महाराष्ट्र

आत्महत्या नहीं - संघर्ष की राह पर चलेंगे !

– गन्ना किसानों का ऐलान

साम्राज्यवादी देशों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और पारराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाइयों, हाईब्रिड बीजों, टर्मिनेटर बीजों, कृषि यंत्रों के बाजार के लिए तथा उनके कारखानों-कम्पनियों के लिए जरूरी कच्चा माल के लिए भारतीय कृषि को साम्राज्यवादियों ने दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों की सहायता से इस्तेमाल करने के लिए चुना. दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों ने सामन्तवाद की सहायता से साम्राज्यवादी देशों की भरपूर सहायता की तथा भारतीय कृषि को साम्राज्यवादियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया. नगदी फसलों पर ज्यादा जोर दिया गया. कपास, गन्ना, सोयाबीन, सूरजमुखी व अन्य तिलहन, मुर्गी पालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा. भारतीय सरकार ने मीडिया के द्वारा इनका बड़े जोर सोर से प्रचार किया गया मानों इनकी कृषि करने से किसान खुशहाल हो जाएंगे. साथ ही अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाइयों, हाइब्रिड बीजों व आधुनिक कृषि यंत्रों की जरूरत के बारे में खूब प्रचार किया गया. एक प्रकार से इनका कृषि में उपयोग करने के लिए किसानों को मजबूर किया गया. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र,आदि राज्यों में 'हरित क्रान्ति' को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया. बढ़े उत्पादन का व्यापक प्रचार कर आत्मनिर्भरता के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा. उत्पादन लागत की तुलना में उत्पादन का प्रतिशत हमेशा छुपाया गया. बस बढ़ता उत्पादन ही दिखाया गया.

लेकिन कुछ सालों में ही सरकार द्वारा किसानों को दिखाए जाने वाला सुनहरा सपना टूटने लगा. पानी, बिजली, कृषि यंत्रों, कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक खादों, बीजों व डीजल की बढ़ती कीमतों से कृषि उत्पादन की लागत बढ़ती गई. इस वजह से हर किसान बैंकों, सूदखोर-महाजनों का कर्जदार हो गया. साल दर साल किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला गया. किसान जब भी खाद, पानी, बिजली, कीटनाशक, बीज व कृषि यंत्रों की कीमतों में कमी और कृषि उपज की मांग में वृद्धि के लिए आन्दोलन करते सरकार उन पर लाठी-गोलियों की बरसात कर किसानों की हत्या पर उतारू हो जाती. मजबूरन किसान कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या करने लगे. आज आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या हजारों में पहुंच गई है.

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ही एक हजार से ज्यादा किसान कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं. आत्महत्याओं की घटनाएं अभी भी जारी हैं. पूरे देश का पेट भरने वाला किसान जब कर्ज न चुकाने की वजह से आत्महत्याएं करने लगे, इससे शर्मनाक व दर्दनाक घटना हो ही नहीं सकती. तब भी हमारे राजनेताओं की सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं. वे इन आत्महत्याओं का दूसरा कारण देखने लगे हैं. महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का तो साफ कहना है कि किसान पैसों की लालच में आत्महत्याएं कर रहे हैं. इस तरह एक गलत तस्वीर पेश की जा रही है. इसके लिए विलासराव देशमुख की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम होगी.

समस्याओं से जूझते विदर्भ और मराठवाड़ा सहनशील किसानों के दुख-तकलीफों तथा सरकार के रवैए को देखते हुए गन्ना उत्पादक किसानों ने साहसिक निर्णय लेते हुए संघर्ष करने की ठान ली है. किसानों का साफ कहना है कि वे चुपचाप रहकर आत्महत्या जैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे. बल्कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे. सरकार ने जहां गन्ने की कीमत 850 रुपए प्रति टन तय की है वहीं किसान 1800 रुपए प्रति टन की मांग को लेकर आन्दोलित हैं. सरकार ने आन्दोलनरत किसानों से सख्ती से निपटने की धमकी दी. लेकिन गन्ना उत्पादक किसानों ने सरकारी धमकियों से न डरते हुए अपने आन्दोलन को और तेज करने के लिए तैयारियां शुरू कर दीं. सरकारी स्तर पर उन्हें हर स्तर पर चेतावनी दी जाने लगी. इन सबकी परवाह न करते हुए किसानों ने अनेक इलाकों में खूब जुझारू संघर्ष चलाया. वाहन जलाया, सरकारी कार्यालयों की जमकर तोड़फोड़ की तथा पुलिस-प्रशासन को खूब छकाया. किसानों के संघर्षों का कोई जल्द अन्त होगा ऐसी कोई सम्भावना नहीं दिख रही है. क्योंकि सरकार के बयान जिस तरह आ रहे हैं उससे लगता है कि सरकार को केवल कारखाने की चिन्ता है, किसानों से उसे कोई हमदर्दी नहीं है.

गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा समस्याओं का समाधान के लिए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना एक सही व क्रान्तिकारी निर्णय है. यह किसानों को आत्महत्या के बदले संघर्ष का रास्ता अपनाने में मददगार होगा. पूरे देश के किसानों के लिए यह सही दिशा-निर्देश का कार्य करेगा. इसके लिए विदर्भ व मराठवाड़ा के गन्ना उत्पादक किसान क्रान्तिकारी अभिनन्दन के पात्र हैं. ✶

(.... पृष्ठ 21 का शेष)

37.	पद्दम सनकी	"	"
38.	लश्के	ईदवाड़ा	"
39.	एक अज्ञात महिला	नेतिकाकिलेर	"
40.	आयती	पेद्दाकोरमा	बीजापुर
41.	बुदरी	"	"
42.	सोमली	"	"
43.	ग्यती	मनकेली	"
44.	सोमली	"	"
45.	परसो मासे (35)	चिन्ना पल्ली	भैरमगढ़
46.	जैनी	नूंगूर	"
47.	बुदरी	कुमुममेट्टा	"
48.	भीमे	परकेली	"
49.	फूलवती	एहकेल	"
50.	सायबो	"	"
51.	सामो	"	"

वक्तव्य

खैरलांजी में दलितों पर हुए पाशविक नरसंहार की निंदा करो !

कानपुर में अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ किए गए अपमान की भर्त्सना करो !

17 नवम्बर 2006

29 सितम्बर 2006 महाराष्ट्र के भण्डारा जिला के मोहाडी तहसील का एक छोटा सा गांव खैरलांजी में मनुवादी सवर्ण मानसिकता के सामन्ती वर्गों ने पाशविकता का नंगा नाच करते हुए दलितों का खून बहाया. एक तरफ देश की सरकारें दलितों के उद्धार के नाम से कानून-दर-कानून बनाते जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ब्रह्मणवादी सामन्ती ताकतें समय-समय पर देश के कोने-कोने में दलितों का कत्लेआम करते जा रही हैं. खैरलांजी में सुरेखा भोतमांगे नामक एक गरीब दलित महिला, जिसने अपनी जमीन पर अधिकार पाने के लिए सवर्ण सामन्ती ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी और जिसने भीषण गरीबी को झेलते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया था, को 'सबक' सिखाने के लिए इस जघन्य हत्याकाण्ड को अंजाम दिया गया. गांव के हिन्दू सवर्णों ने, जिन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है, 45 वर्षीया सुरेखा भोतमांगे और उसकी 18 वर्षीया बेटी प्रियंका भोतमांगे के साथ सामूहिक बलात्कार कर बुरी तरह मार डाला. सुरेखा के दो बेटों रोशन (23) और सुधीर (21) को उन्होंने चाकुओं से गोद-गोद कर मार डाला. मारने से पहले इन दोनों भाइयों और उनकी मां और बहन को नंगा कर अकथनीय एवं मानवता को कलंकित करने वाली यातनाएं दीं, जिनके बारे में लिखने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे. यह सब गांव के चौपाल में सबके सामने होता रहा और पूरा गांव इसे देखता रह गया, जहां हिन्दू सवर्ण जातियों का वर्चस्व है. इस परिवार का पुरुष मुखिया, सुरेखा के पति भैयालाल ने इस सारे अमानवीय घटनाक्रम को थोड़ी ही दूर से अपनी आंखों से देखा, पर किसी तरह अपनी जान बचा ली. वही उस परिवार का एक मात्र सदस्य है, जो अब जिन्दा है. मानवता को कलंकित करने वाले इस जघन्य अपराध के बारे में पुलिस को उसी शाम खबर मिलने के बावजूद इस दलित परिवार को बचाने या दोषियों की तुरन्त धरपकड़ करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली. इस घटना ने फिर एक बार हमें दिखा दिया कि आज भी ग्रामीण भारत में सवर्ण सामन्ती ताकतें किस तरह हावी हैं.

इस घटना के बाद, कुछ देर से ही सही, देश भर में और खासकर, महाराष्ट्र के कोने-कोने में जनता के विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ. इस मामले पर सीबीआई जांच करवाने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांगें जोर-शोर से उठी. लेकिन पुलिस-प्रशासन ने सामन्ती व सवर्ण वर्गों के पक्षधर होने का सबूत पेश करते हुए नागपुर, अमरावती, शोलापुर आदि जगहों में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां चलाईं जिसमें कई लोगों की जानें गईं. मीडिया के एक हिस्से ने भी तथाकथित सवर्णों का पक्ष लेते हुए इस हत्याकाण्ड के लिए अवैध सम्बन्धों को कारण बताकर जनता को गुमराह करने की भरसक कोशिश की. दूसरी तरफ शासन-प्रशासन ने इस हत्याकाण्ड के खिलाफ भड़क रहे जन आक्रोश के पीछे नक्सलवादियों के हाथ होने का झूठा आरोप लगाकर उसे नाजायज ठहराने की कोशिश की. माना कि यह आरोप सच भी है, तो क्या किसी न्यायपूर्ण आन्दोलन में नक्सलवादियों के शामिल होने से वह आन्दोलन नाजायज हो जाता है? अगर किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही 'नक्सलवाद' है तो उसमें गलत क्या है? क्या किसी न्यायपूर्ण आन्दोलन के पीछे 'नक्सलवादी हैं' कहने मात्र से उसका दमन करने के लिए वैधता मिल जाती है? जिस तरह अमेरिकी व ब्रितानी साम्राज्यवादियों के खिलाफ दुनिया के किसी भी हिस्से में, खासकर मध्य-पूर्व में होने वाली हर कार्रवाई के पीछे 'अल कायदा का हाथ' खोजा जाता है, ठीक उसी तरह आज भारत की सरकारें भी हर जगह 'नक्सलवादियों का हाथ' ढूंढ़ रही हैं. यह सब लुटेरे शासक वर्ग और मीडिया इसलिए प्रचारित कर रहे हैं ताकि खैरलांजी नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाने वाली शोषित-उत्पीड़ित दलित जनता का दमन किया जा सके और इस दमन को जायज ठहराया जा सके.

खैरलांजी दलित नरसंहार के बाद खासकर महाराष्ट्र में जोर शोर से उठे दलितों के संघर्षों का भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी तहेदिल से समर्थन करती है. हम इस मौके पर कानपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले के साथ किए गए अपमान की भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. हम दण्डकारण्य, छत्तीसगढ़ एवं विदर्भ की मेहनतकश जनता, बुद्धिजीवियों एवं जनवादी व दलित संगठनों से अपील करते हैं कि आप खैरलांजी नरसंहार के खिलाफ व्यापक एवं जुझारू विरोध प्रदर्शनों को तब तक जारी रखें जब तक कि इस घृणित हत्याकाण्ड को अंजाम देने वालों और उनका सहयोग करने वाले पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती. हम इस मौके पर तमाम शोषित-दलित जनता का आह्वान करते हैं कि दलितों पर हो रहे हमलों एवं कत्लेआमों को रोकना है तो देश के कई हिस्सों में हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी नव जनवादी क्रान्ति के साथ तालमेल रखना तथा उसमें शामिल होना ही एक मात्र रास्ता है ताकि वर्तमान शोषणकारी, दमनकारी व उत्पीड़नकारी व्यवस्था का जड़ से सफाया किया जा सके. सामन्तवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंककर ही हम एक खुशहाल नव भारत का निर्माण कर सकते हैं जो समतामूलक, आत्मनिर्भर व आजाद हो और जहां लैंगिक, नस्लीय, जातिगत व धार्मिक भेदभावों का नामोनिशान तक न हो.

(कोसा),
सचिव,
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भाकपा (माओवादी)

वक्तव्य

एर्राबोर घटना के लिए रमन सरकार जिम्मेदार !

दिनांक – 28 जुलाई 2006

2006 जुलाई 16–17 की दरमियानी रात हमारी पीएलजीए की अगुवाई में करीब एक हजार आदिवासी जनता ने एर्राबोर स्थित तथाकथित राहत शिविर पर धावा बोल दिया. दन्तेवाड़ा जिले के बीजापुर तहसील में पिछले एक साल से और कोंटा तहसील में पिछले 7 महीनों से 'सलवा जुडूम' के नाम पर जारी बर्बरतापूर्ण व आतंकी दमन अभियान में नगा पुलिस, छग पुलिस, सीआरपीएफ, एसपीओ और गुण्डों ने अब तक करीब 250 निरीह लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनका न तो कोई एफआईआर है न ही कोई रिकार्ड. 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ इन पशु बलों ने सामूहिक बलात्कार कर करीब 35 महिलाओं की हत्या की. 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़ों तक को इन दरिंदों की गोलियों का शिकार होना पड़ा. करीब 700 गांवों के 3 हजार से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया गया. 500 करोड़ रुपए की सम्पत्ति लूट ली गई या तबाह कर दी गई. गाय, बैल, बकरे, मुरगे सब कुछ लूट लिए गए. कई लोगों की हत्या कर लाशों को इन्द्रावती नदी में बहा दिया गया. बस्तर क्षेत्र में पिछले 25 सालों से जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया कर इस क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूट का चारागाह में तब्दील करने के मकसद से जारी इस सर्वाधिक जुल्मी अभियान के चलते अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं. इनमें से करीब 50 हजार लोग सरकारी बलों के दबाव में 'राहत शिविरों' में बन्दियों की तरह जिन्दगी गुजार रहे हैं तो बाकी लोग जंगलों में दर–दर भटक रहे हैं. बस्तर के आदिवासियों को जंगलों से बाहर निकालकर बन्दूक की नोक पर बन्दी शिविरों में रखने की एक सोची–समझी साजिश के तहत ही सामन्ती मुखिया महेन्द्र कर्मा और दलाल रमन सरकार के नेतृत्व में इस अभियान को चलाया जा रहा है. महेन्द्र कर्मा और रमन सिंह टाटा, एस्सार, जिन्दल, मित्तल जैसे बड़े पूंजीपति घरानों से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर एक षड़यंत्र के तहत इसे 'शांति अभियान' या 'आदिवासियों का सस्फूर्त आन्दोलन' का नाम देकर संचालित कर रहे हैं. बस्तर में हजारों पुलिस व अर्ध सैनिक बलों को तैनात कर, 3 हजार से ज्यादा आदिवासी नौजवानों को एसपीओ के रूप में नियुक्त कर हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी, आदि जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है. इन सबसे त्रस्त बस्तर के हजारों आदिवासियों के दिल में भड़के आक्रोश का परिणाम ही था एर्राबोर की घटना.

दरअसल तथाकथित राहत शिविरों का संचालन एसपीओ और गुण्डों (जिन्हें सलवा जुडूम कार्यकर्ता कहा जाता है) के द्वारा किया जा रहा है. वे जनता को दबाकर रखते हैं और उसकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखते हैं. उन्हें हांककर अपने हमलों में शामिल करते हैं. जो लोग इन बन्दी शिविरों से वापस जाना चाहते हैं उन्हें डरा–धमकाकर या मार–पीटकर रोकते हैं. पुलिस बल राहत शिविरों को सुरक्षा नहीं देते बल्कि अपने थाने व कैम्प के इर्द–गिर्द मौजूद 'राहत शिविर' से वे खुद को सुरक्षित रखते हैं. उसमें रहने वाले लोगों को वे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं. गुण्डे व एसपीओ पुलिस बलों की आंख और कान की तरह काम कर रहे हैं, जिनका सफाया किए बिना जनता का इस व्यापक तबाही से बचना मुश्किल है. इस हमले के पीछे जनता और उसकी अगुवाई कर रही पीएलजीए का मकसद इन्हीं आतंकी गुण्डों व विशेष पुलिस अधिकारियों का सफाया करना था जिन्होंने कोंटा, दोरनापाल आदि इलाकों में लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था. वे पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के साथ गांवों में आकर आंतक का ताण्डव मचा रहे थे. गांव में जो भी मिलता उसे मार डालना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, घरों को जलाना, सम्पत्ति को लूटना, खेती करने नहीं देना, खेतों में काम करने वालों पर गोलियां बरसाना, झूठी मुठभेड़ की कहानियां गढ़ना, आदि तमाम दमनकारी कुकृत्यों से आदिवासी जनता का दिल दहल उठा. इसीलिए इस हमले में एक हजार से ज्यादा जनता ने शिरकत की. अब तक सैकड़ों गांवों के हजारों घरों को जलाने व तबाह करने में सक्रिय रूप से शामिल गुण्डों व एसपीओं के अड्डों में आग लगाकर उन्हें उनकी ही भाषा में सबक सिखाने की मांग इस इलाके की समूची जनता से जोर–शोर से उठ रही थी. साथ ही साथ, बन्दूक की नोक पर उन 'राहत शिविरों' में जी रही असहाय व बेबस जनता को मुक्त कराना भी हमारा लक्ष्य था. हमारे पीएलजीए के कॉमरेडों ने जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही सीआरपीएफ व थाना पुलिस पर हमला कर उन्हें घण्टों निष्क्रिय बनाए रखा था और जनता गुण्डों व एसपीओं पर टूट पड़ी. गुण्डों व जनता के बीच हुई घमासान लड़ाई में 30 से ज्यादा गुण्डे व एसपीए मारे गए और जनता व पीएलजीए के कुछ साथी घायल हुए. रात के अंधेरे में हुई उस भीषण लड़ाई से मची अफरातफरी के चलते गलती से 2 बच्चे और दो निर्दोष महिलाएं भी मारी गई थीं, जोकि अत्यंत दुःखद है. इस कार्रवाई में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हमारे सैनिकों व जनता ने **इरादतन** नहीं मारा. बाद में जनता और जन सैनिक 42 लोगों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए थे. उनमें से 6 लोगों का सफाया कर दिया गया, जबकि बाकी को छोड़ दिया गया क्योंकि वे कट्टर अपराधी नहीं थे और किसी को नाहक मारना हमारा इरादा नहीं था.

इस घटना के बाद सरकार ने मीडिया के जरिए हमारी पार्टी के खिलाफ एक व्यापक दुष्प्रचार मुहिम छेड़ दी. जबसे सलवा जुडूम शुरू हुआ, तभी से सरकार ने मीडिया का सुनियोजित तरीके से अपने पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू किया. टीवी चैनलों ने राहत शिविर में जनता और पीएलजीए सैनिकों द्वारा जलाए गए गुण्डों व एसपीओ के घरों की फुटेज बार–बार दिखाई. लेकिन पिछले एक साल से जनता के ऐसे हजारों मकान सलवा जुडूम गुण्डावाहिनी व पुलिस–अर्ध सैनिक बलों के द्वारा जलाए गए थे, जिनकी एक भी तसवीर दिखाने की कोशिश विजुअल मीडिया ने नहीं की. लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहलाने वाली मीडिया की भूमिका आज बेहद संदिग्ध बन गई है. किसी भी अखबार ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस हमले में हजार से ज्यादा आदिवासी लोग क्यों शामिल हुए होंगे. क्यों वे ऐसे कठोर कदम उठाने पर मजबूर हुए होंगे.

सुरक्षा सलाहकार केपीएस गिल ने एक अखबार को दिए

साक्षात्कार में आरोप लगाया कि जनता और जन सैनिकों ने एक महिला एसपीओ को मारने से पहले सामूहिक बलात्कार किया था. गृहमंत्री रामविचार नेताम, अपर मुख्य सचिव और दन्तेवाड़ा कलेक्टर केआर पिसदा ने भी इस आरोप को दोहराया. 'उलटा चोर कोतवाल को डांटा' वाला कहावत इनके लिए सटीक बैठता है. एक महिला आइपीएस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में सर्वोच्च अदालत द्वारा सजा भुगत चुके केपीएस गिल हम पर ऐसा नीचतापूर्ण आरोप लगाकर सूरज पर थूंकने का दुस्साहस कर रहे हैं. खुद बलात्कारी पुलिस बलों का नेतृत्व करने वाले गृहमंत्री जी और अपर मुख्य सचिव (गृह) बीकेएस रे हम पर बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं. पिछले एक साल से जारी सलवा जुडूम के तहत 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले, यहां तक कि एक गर्भवती महिला (वेड़िंजे नंगी, ग्राम मूकावेल्ली, भैरमगढ़ विकासखण्ड, 5 अक्टूबर 2005) की कोख को चीरकर भ्रूण को बाहर निकालकर फेंक देने वाले खुद पुलिस बल और पुलिस-प्रशासन द्वारा पाले-पोसे जा रहे गुण्डे व एसपीओ ही थे. मोडियम सुक्की (ग्राम पेद्दा कोरमा), कुरसम लक्के (ग्राम पेद्दा कोरमा), मड़काम सन्नी (गर्भवती - ग्राम एटेपाड़), वेडिंजे मल्ली (ग्राम मूकावेल्ली), बोग्गम सोमवारी (ग्राम कोटलू) - इन तमाम महिलाओं के साथ पहले सामूहिक बलात्कार करके बाद में इनकी हत्या करने वाले खुद नगा पुलिस, सीआरपीएफ जवान और एसपीओ थे. सरकारी बलों की निर्ममता और पाशविकता की जीवन्त मिसाल - श्रीमती मासे परसो (उम्र 35 साल, गांव चिन्ना पल्ली, भैरामगढ़ विकासखण्ड) की दर्दभरी दास्तान सुनिए. 1 फरवरी की रात सलवा जुडूम के 10 गुण्डों ने इस गांव पर हमला कर मासे परसो के साथ सामूहिक बलात्कार कर उनके गले को चाकुओं से गोदकर बुरी तरह घायल कर दिया था. उसे मरी समझकर वहीं छोड़कर चले गए थे. अगले दिन वहां पहुंचे पीएलजीए के सैनिकों ने तुरन्त इस महिला का इलाज किया तो उसकी जान तो बच गई, पर स्वरपेटी क्षतिग्रस्त होने से वह अब बोल नहीं पा रही है. ऐसी दर्जनों महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्हें पिछले एक साल के दौरान पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों व गुण्डावाहिनी ने अपने वहशीपन का शिकार बनाया. विडम्बना यह है कि इन तथ्यों को कोई भी अखबार प्रकाशित करने को तैयार नहीं है. सलवा जुडूम पर एक निष्पक्ष जांच बिठाने से ऐसे कई तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए न तो केन्द्र सरकार न ही राज्य सरकार तैयार है.

कामरेड मोति (20) छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश सीमा पर हत्यारे ग्रेहाउण्ड्स बलों पर पीएलजीए द्वारा किए गए हमले में शहीद हुई।

एर्राबोर घटना में गलती से दो बच्चों और दो निर्दोष महिलाओं की मौत होने पर हम पर कीचड़ उछालने वाले पुलिस-प्रशासन क्या इस सवाल का जवाब देंगे कि किसके कहने पर मूकावेल्ली गांव में डेढ़ साल के बच्चे के सिर में नगा पुलिस ने गोली मारी थी. क्यों ग्राम हरियाल (चेरली) में 10 साल का बच्चा कड़ती कुम्माल को मार डाला गया था? 14 साल का किशोर बारसे सोनू (ग्राम परालनार) का क्या कसूर था कि उन्हें निर्ममता के साथ मार डाला गया था? ग्राम सेन्ड्रा में 6 और 8 साल के दो आदिवासी बच्चों पर सीआरपीएफ ने गोलियां क्यों दागीं? क्या रमन सिंह यह भूल गए कि वे आज छत्तीसगढ़ में जिस भाजपा का शासन चल रहा है, उसके हाथ 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए दर्जनों बच्चों के खून से रंगे हैं? क्या महेन्द्र कर्मा और रमन सिंह इन हत्याओं के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार होंगे?

जैसे कि हम शुरू से ही कह रहे हैं, सलवा जुडूम 'शांति अभियान' नहीं है, न ही वह जनता का सस्फूर्त आन्दोलन. यह टाटा, एस्सार, जिन्दल जैसे बड़े पूंजीपतियों और अमेरिका, जापान जैसी साम्राज्यवादी ताकतों के हित में चलाया जा रहा दमनकारी अभियान है. इसका मकसद है बस्तर की जनता को जंगलों से बाहर लाकर बन्दी शिविरों में ठूंसकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूटखसोट का रास्ता साफ करना. इसके लिए वे सैकड़ों-हजारों लोगों की हत्या करने से भी नहीं चूकेंगे. लेकिन बस्तर की संघर्षशील जनता इस षड्यंत्र को जरूर चकनाचूर कर देगी. कुछ मध्यमवर्गीय उदारपंथी बुद्धिजीवी यह कहते हुए कि ''गोली इधर से चले या उधर से, मर तो आदिवासी रहे हैं'', जनता के जायज प्रतिरोधी संघर्ष पर उंगली उठा रहे हैं. लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि सलवा जुडूम के खिलाफ बस्तर में जारी न्यायपूर्ण जन-प्रतिरोध का विरोध कर वे लुटेरे शासकों के ही हाथ मजबूत कर रहे हैं. जन-प्रतिरोध को समाप्त करने का मतलब है जनता के अस्तित्व को ही खतरे में डालना. यह जंग है - सलवा जुडूम से बेघरबार हुए हजारों आदिवासियों की, बलात्कार का शिकार हुई बीसियों आदिवासी बहनों की, अपने बेटों व बेटियों को खोने के गम में खून के आंसू बहाने वाली अनगिनत आदिवासी माताओं की, अपना जल-जंगल-जमीन को बचाने के लिए छटपटा रहे हजारों बस्तरियों की, झूठे व भ्रष्ट लोकतंत्र का खात्मा कर सच्चे व नए लोकतंत्र की नींव डाल रहे मेहनतकश किसान-मजदूरों की. इसलिए हम तमाम जनवाद पसन्द लोगों से अपील करते हैं कि वे सलवा जुडूम को नेस्तनाबूद कर बस्तर के आदिवासी अवाम को तबाही, विस्थापन और मौत से बचाने के लक्ष्य से जारी हमारे प्रतिरोधी संघर्ष का समर्थन करें. हमारी कार्रवाइयों के दौरान होने वाली गलतियों के लिए हमारी आलोचना जरूर करें, हम जरूर स्वीकारेंगे और खुद को सुधारेंगे, पर इस वजह से जनता के जायज प्रतिरोधी संघर्ष का विरोध मत करें.

हम जनता व जनवादी संगठनों से अपील करते हैं कि वे राज्य व केन्द्र सरकारों पर दबाव डालें कि सलवा जुडूम के नाम पर आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने के खूनी खेल को तत्काल बन्द किया जाए; अब तक सरकारी बलों व गुण्डावाहिनी द्वारा किए गए कत्लेआम, बलात्कार, लूटपाट व आगजनी की तमाम घटनाओं पर निष्पक्ष जांच बिठाई जाए; एसपीओ नाम से आदिवासी युवकों की नियुक्ति तुरन्त बन्द किया जाए, उनसे हथियार वापस लिए जाएं; नगा बटालियन समेत तमाम अर्ध सैनिक बटालियनों को वापस भेजा जाए; राहत शिविरों को बन्द कर आदिवासियों को उनके गांव वापस भेजा जाए.

(कोसा) सचिव,

(गुड़सा ऊसेंडी) प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भाकपा (माओवादी)

‘सलवा जुडूम’ के नाम पर पौने दो साल से बस्तर में जारी व्यापक आतंक, कत्लेआम, लूट और आगजनी का जवाब है ‘रानीबोदली’ प्रतिरोधी कार्रवाई !

इस शानदार हमले को सफल बनाने हेतु अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर करने वाले जांबाज वीर योद्धा कॉमरेड्स मोहन, भगत, कैलास, लिंगाल, चैतू और भीमाल की बहादुराना शहादत जिन्दाबाद !

14–15 मार्च की दरमियानी रात पीएलजीए ने पश्चिम बस्तर डिवीजन (बीजापुर पुलिस जिला) के रानीबोदली पुलिस चौकी पर शानदार व ऐतिहासिक हमला किया. इस हमले में 39 एसपीओ समेत 55 पुलिस बल कुत्ते की मौत मारे गए, जबकि 11 अन्य घायल हो गए. घायलों में 9 एसपीओ थे. इस कैम्प से पीएलजीए ने कुल 33 हथियार छीन लिए. जिनमें 1 दो इंच का मोर्टार, 3 एके–47, 13 एसएलआर शामिल हैं. लेकिन पीएलजीए को यह जीत आसानी से नहीं मिली. छह कॉमरेडों ने अपने अनमोल प्राणों की आहुति देकर यह इतिहास रचा है. इन जांबाज शहीद कॉमरेडों के नाम इस प्रकार हैं – कॉमरेड मोहन (पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी सदस्य और डिवीजनल कमाण्डर–इन–चीफ), कॉमरेड भगत, कॉमरेड कैलास, कॉमरेड लिंगाल, कॉमरेड चैतू और कॉमरेड भीमाल. इन पराक्रमी कॉमरेडों ने अपनी जान की रत्ती भर भी परवाह न करते हुए, दुश्मन को ललकारते हुए अनुपम शूरता एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के बलों की धज्जियां उड़ा दीं. (चूंकि यह खबर हमें पत्रिका के छपते–छपते मिली है, इसलिए इन शहीदों की जीवनियां इस अंक में नहीं दे पा रहे हैं. अगले अंक में हम इस कमी को जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे. – सं) भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में दुश्मन के सशस्त्र बलों का इतनी बड़ी संख्या में सफाया करने का सम्भवतः यह पहला हमला था.

39 एसपीओ समेत 55 पुलिस बलों का सफाया – 11 अन्य घायल

33 हथियारों के जखीरा पर जन बलों का कब्जा

पीएलजीए के 6 जांबाज लाल योद्धाओं की शौर्यपूर्ण कुरबानी

करीब पौने दो साल पहले जून 2005 में बीजापुर पुलिस जिले के अम्बेली गांव, जो ठीक रानीबोदली गांव के करीब बसा हुआ है, में जन विरोधी सामन्ती गुण्डों और पुलिस बलों ने आदिवासी जनता पर हमला किया था. वहीं से तथाकथित ‘सलवा जुडूम’ की शुरूआत हुई थी जिसका वास्तविक अर्थ है ‘सामूहिक शिकार’. आदिवासियों के सस्फूर्त व शांतिपूर्ण अभियान के रूप में प्रचारित इस सर्वाधिक जुल्मी अभियान में तबसे लेकर अब तक 400 से ज्यादा आदिवासियों को सीआरपीएफ, नगा पुलिस, मिजो पुलिस, राज्य पुलिस, एसपीओ और ‘सलवा जुडूम’ गुण्डा गिरोहों ने निर्ममतापूर्वक मार डाला. 10 साल के किशोर से लेकर 60 साल के बूढ़ों तक को इनकी बर्बरता की भेंट चढ़ा दी गई. कई लोगों को काटकर लाशें इन्द्रावती नदी में बहा दी गईं. 100 से ज्यादा युवतियों एवं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. कइयों को मार डाला गया. सैकड़ों गांवों में हजारों घर जला डाले गए. हजारों लोगों को जबरन ‘राहत शिविरों’ में घसीट लाकर नारकीय जिन्दगी जीने को मजबूर बनाया गया. सरकार ने मीडिया को अपने कब्जे में रखकर इन सभी सच्चाइयों को दबाए रखा. जनता की मांग पर और उसकी सक्रिय भागीदारी से माओवादी कार्यकर्ता जब कोई जवाबी कार्रवाई करते हैं उसी को बढ़ा–चढ़ाकर एकतरफा खबरें छापने का मानों रिवाज बन पड़ा. जो सच बोलने और लिखने की हिम्मत रखते हैं उन्हें न सिर्फ मारने की धमकियां दी गईं, बल्कि कई पत्रकारों की पिटाई कर दी गई. यहां तक कि जन–प्रतिनिधियों, व्यापारियों, ड्राइवरों, शिक्षकों को भी सलवा जुडूम गुण्डा गिरोहों व एसपीओ द्वारा मारा–पीटा गया, जबकि पुलिस अधिकारी तमाशा देखते रहे. कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ भी छीना–झपटी जैसा अभद्र व्यवहार किया गया. खासकर नगा और मिजो जवान आतंक का पर्याय बन कर दर्जनों आदिवासी मां–बहनों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया. इन सब अपमानों, अत्याचारों एवं जुल्मों से बस्तर की हजारों आदिवासी जनता के दिलों में प्रतिशोध की आग सुलगती रही. और उसी आग ने 15 मार्च 2007 के भोर में रानीबोदली पुलिस चौकी को तबाह कर डाला. इसके लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों समेत टाटा, एस्सार, जिन्दल जैसे दलाल पूंजीपति, महेन्द्र कर्मा, रमन सिंह जैसे दलाल एवं चोर नेता जिम्मेदार हैं जो आदिवासियों के खून के प्यासे हैं.

इस हमले के कुछ ही घण्टे पहले पश्चिम बंगाल के नंदिग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अपनी जमीनें देने से इंकार करने वाले 14 निहत्थे किसानों को सामाजिक फासीवादी माकपा सरकार के आदेश पर पाशविक पुलिस बलों एवं गुण्डों ने गोलियों से भून डाला था. करीब 60 लोगों को घायल किया था. यह महज इत्तेफाक नहीं है. आज भारत में दलाल पूंजीपतियों एवं साम्राज्यवादियों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हितपोषण करने वाली सरकारें आदिवासियों और अन्य शोषित किसानों को विस्थापित करने पर तुली हैं. इसका विरोध करने पर गोलियां बरसा रही हैं, जैसे कि कलिंगनगर, सिंगूर और अब नंदिग्राम किया गया. बस्तर को टाटा, एस्सार, जिन्दल, आदि बड़े पूंजीपतियों की लूट का चारागाह बनाने के लिए ही ‘सलवा जुडूम’ चलाया जा रहा है. लेकिन देश के विभिन्न इलाकों में भाकपा

(माओवादी) के नेतृत्व में संघर्षरत जनता सामन्तवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुकी है. प्रतिक्रियावादी शासक कलिंगनगर, नंदिग्राम, सलवा जुडूम जैसे नरसंहारों को अंजाम दे रहे हैं, तो जनता और जनता की लड़ाकू सेना पीएलजीए को रानीबोदली जैसे हमले करने का पूरा-पूरा अधिकार है.

हाल ही में सम्पन्न हमारी पार्टी - भाकपा (माओवादी) की ऐतिहासिक एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस द्वारा सौम्पे गए नए एवं उन्नत कार्यभारों से लैस हमारी बहादुर पीएलजीए के वीर कमाण्डरों के नेतृत्व में सौ से ज्यादा लाल योद्धाओं और कोया भूमकाल मिलिशिया के सदस्यों ने जनता की सक्रिय मदद से इस जबर्दस्त हमले को कामयाबी के साथ अंजाम दिया. इस कैम्प के चारों तरफ पास-पास में कई अन्य पुलिस थाने एवं कैम्प मौजूद होने के बावजूद भी योजनाबद्ध तरीके से हमारे जांबाज जनयोद्धा बिजली सी तेजी से जुल्मी पुलिस बलों और आतंकी एसपीओ पर इस तरह टूट पड़े कि उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं मिला. पूरे 55 पुलिस बलों का सफाया कर 11 को घायल कर दिया गया. जनता को आतंकित करने एवं मार डालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 33 हथियार पीएलजीए ने जब्त कर लिए. दण्डकारण्य में माओवादी आन्दोलन का सफाया कर इस पूरे इलाके को साम्राज्यवादियों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूट के चारागाह में तब्दील करने का दिवास्वप्न देख रहे तमाम प्रतिक्रियावादी शासकों को हम यहां की शोषित जनता की तरफ से इस मौके पर चेतावनी दे रहे हैं कि सलवा जुडूम को तुरन्त बन्द कर एसपीओ को वापस भेज दें और पौने दो साल से जारी पाशविक हत्याकाण्ड व विध्वंसकाण्ड को रोक दें वरना रानीबोदली जैसी कार्रवाइयां दोहराई जाएंगी. हम मांग करते हैं कि बस्तर से नगा, मिजो बटालियन समेत तमाम अर्ध-सैनिक बलों को वापस लें. झूठी मुठभेड़ों को बन्द करें. जनता की हत्या करने, घरों को जलाने, लूटने और महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले पुलिस बलों और गुण्डों को दण्डित करें. हम यह भी ऐलान करते हैं कि हजारों आदिवासियों को उजाड़ने वाली टाटा (लोहंड़ीगुड़ा) और एस्सार (भांसी) कम्पनियों को बस्तर में कोई जगह नहीं है.

हम इस मौके पर एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारियों)से अपील करते हैं कि आप जाने-अनजाने में जनता के खिलाफ बन्दूक उठाकर जुल्मों एवं अत्याचारों को अंजाम जो दे रहे हों, इस पर जरा पुनरविचार कीजिए. रानीबोदली हमले में एसपीओ ही ज्यादा संख्या में मारे गए हैं, इससे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए. इस घटना से आपको समझ में आया ही होगा कि चारों तरफ फैले हुए सैकड़ों पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों की छावनियां भी आपको जनता के आक्रोश से नहीं बचा सकेंगी. दरअसल सरकार आपको आगे रखकर आपके अपने ही माता-पिता एवं भाई-बहनों को मरवाने का घिनौना खेल खेल रही है. इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप यह नौकरी छोड़ दें. अपने ही भाई-बन्धुओं को अपनी बन्दूक का निशाना मत बनाइए. अपने अपराधों एवं गलतियों के लिए जनता से क्षमायाचना कीजिए. यह मत सोचिए कि जनता और पीएलजीए आपको मार देंगी. आप अगर सच्चे मन से माफी मांगते हैं और सामान्य जिन्दगी जीना चाहते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यह हमारा वादा है. अभी तक ऐसे दर्जनों लोग अपनी नौकरी एवं हथियार छोड़कर अपने-अपने गांव लौट चुके हैं. हमारी अपील के बावजूद भी अगर आप मानवता को कलंकित करने वाले 'सलवा जुडुम' अभियान में बने रहना चाहते हैं और पुलिस व अर्ध सैनिक बलों का साथ देना चाहते हैं तो जनता एवं उसकी रक्षा में जी-जान लगा देने वाली पीएलजीए के सामने इस तरह की प्रतिरोधी कार्रवाइयों को तेज करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता. सही फैसला लीजिए, अभी भी वक्त है. ✶

सरकार आखिर एक सीडी से क्यों डरती है?

'बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है!' एक जमाने में भगतसिंह और उसके साथियों ने यही बात दोहराकर नेशनल असेम्ब्ली में बम फोड़ा था, तब जाकर अंग्रेजी हुक्मरानों के कान खड़े हो गए थे. ठीक इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एक सीडी के माध्यम से माओवादियों ने मार्च 2006 में कुछ ऐसा ही धमाका कर दिया. अपने प्रचार माध्यमों (टीवी, रेडियो और अखबारों) के जरिए सलवा जुडूम को 'शांति मिशन' और 'माओवादियों के खिलाफ जनता का सस्फूर्त आन्दोलन' कहकर दुष्प्रचार की मुहिम छेड़कर सरकार ने कई मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों और संघर्ष इलाकों के बाहर रहने वाली आम जनता को लगभग बहरा ही बना दिया था. ऐसे में माओवादी क्रान्तिकारियों को सलवा जुडूम की असलियत दुनिया को बताने के लिए सीडी का सहारा लेना पड़ा. सलवा जुडूम के द्वारा जलाए गए गांवों, मारे गए लोगों और अत्याचार की शिकार महिलाओं के सम्बन्ध में फिल्माई गई डाक्युमेन्टरी - ''सलवा जुडूम नहीं सरकारी जुल्म'' - की सीडियों को माओवादी कार्यकर्ताओं ने रायपुर शहर में जब वितरण करना शुरू किया, विधानसभा में खूब शोर-शराबा मच गया. इन सीडियों को विधायकों और मंत्रियों के नाम भी भेजा गया था. इससे सलवा जुडूम का सरगना महेन्द्र कर्मा और उसके सहयोगी बौखला उठे. सीडी भेजने वालों की पतासाजी करने में सारा खुफिया तंत्र जुट गया. पक्ष-विपक्ष के सारे लुटेरे नेता चिल्लाने लगे कि जब नक्सली विधायक विश्रामघर तक सीडी पहुंचा सकते हैं तो कल उसमें बम भी फोड़ सकते हैं. तुरन्त ही सीडी भेजने वाले संदिग्ध माओवादी की पोर्ट्रेट तैयार करवाकर सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया. सारे नेताओं के बंगलों पर सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता बनाया गया. सैकड़ों अतिरिक्त कमाण्डो व नगा जवानों को उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया. लेकिन किसी ने खुलकर यह बताने की हिम्मत नहीं की कि आखिर में उस सीडी में ऐसी क्या बात थी जिससे वे इतना भयभीत हो गए.

सरकार आमतौर पर यह रटती रहती है कि वह लोकतंत्र पर विश्वास रखती है और माओवादी लोकतंत्र के विरोधी है. लेकिन लोकतंत्र के इन स्वयंभू ठेकेदारों की पोल तब खुल जाती है जब वे एक सीडी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते; सीडी में दर्शाए गए गांवों और लोगों के सम्बन्ध में कोई निष्पक्ष जांच के लिए तैयार नहीं होते; और उलटे सीडी बांटने वालों की धरपकड़ का अभियान छेड़ देते हैं.

आखिर सरकार एक सीडी से क्यों इतना डरती है? क्योंकि वह सच्चाई से डरती है. वह डरती है कि इससे कहीं जनता को सच्चाई का पता न चल जाए ! ✶